बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

मुख्य संवाददाता : इन्द्रजीत सिंह मो. 9582093548

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 21 ● अंक: 234 ● नई दिल्ली ● वीरवार 28 अप्रैल 2022 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष

मो. 08750202102

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

घर में फंदे पर झूलता मिला शव; डेयरी चलाता था, 2 बच्चों का पिता था

रेवाड़ी । हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक डेयरी संचालक ने खुदकुशी कर ली है। उसका शव घर में ही एक कमरे में फंदे पर झूलता मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिटी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार, रेवाड़ी शहर के मोहल्ला गुर्जरवाड़ा निवासी चेतन (32) ने अपने घर में ही डेयरी की हुई थी। बुधवार की सुबह उसका शव एक कमरे में फंदे पर झूलता मिला। घर के लोगों ने उसे फांसी पर लटका देख सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया तथा नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक चेतन के 2 लड़के हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि उसने खुदकुशी क्यों की। पुलिस जांच में जुटी है। पड़ोसियों की मानें तो घर में सबकुछ ठीक चल रहा था। फिर भी उसने आत्महत्या क्यों की, यह जांच का विषय है।

आलोचना नहीं, प्रार्थना कर रहा हूं, पीएम मोदी ने फोड़ा विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर महंगाई बम

***मोदी ने उन राज्यों ने नाम गिनाए जिन्होंने पेट्रोल-डीजल पर वैट नहीं घटाया**

***मोदी बोले कि मुंबई में पेट्रोल के दाम 120 से ज्यादा हैं**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर बात की. यहां उन्होंने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को वैट ना घटाने के लिए घेरा.

नई दिल्ली ।

पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों से तेल की कीमतों में कटौती करने का अनुरोध किया है. कोरोना पर मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कॉपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के तहत के तहत राज्यों से वैल्यू ऐडड टैक्स (वैट) घटाने की अपील की है. देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर पीएम मोदी ने ऐसे राज्यों का भी हवाला दिया, जिन्होंने तेल की कीमतों पर वैट घटाया है.पेट्रोल-डीजल में बढ़ोतरी के दौरान वैट कम नहीं करने वाले राज्यों को लेकर पीएम मोदी ने कहा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चर्चा कर रहा हूं. पीएम मोदी ने कहा, कुछ राज्यों ने नहीं सुनी (ईंधन पर वैट कम करने को लेकर). महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड, केरल ने कुछ कारणों की वजह से इसे अनसुना कर दिया. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद कुछ राज्यों ने पेट्रोल, डीज़ल पर टैक्स में कटौती नहीं की, यह लोगों के साथ अन्याय है. पीएम मोदी ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह यूक्रेन-रूस युद्ध को बताया है. पीएम मोदी ने यह टिप्पणी ऐसे समय पर की है, जब आम लोग सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल-डीजल की हर रोज बढ़ती कीमतों से जूझ रही है. विपक्ष भी इसे लेकर सरकार पर हमलावर है. कॉपरेटिव फेडलिज्म की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश ने इसी भावना के साथ कोरोना से एक लंबी जंग लड़ी है और आर्थिक मुद्दों को लेकर भी यही रवैया अपनाना चाहिए. दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति चल रही है. पीएम मोदी ने कहा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चर्चा कर रहा हूं. कुछ कारणों से महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड ने तेल पर वैट नहीं घटाया है. इस वजह से उसका बोझ नागरिकों पर ही पड़ रहा है. आगे पीएम ने कहा, क्या कर्नाटक ने टैक्स नहीं घटाया. उसने पिछले छह महीनों के दौरान राजस्व में 5,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त संग्रह किया होगा. गुजरात ने भी 3,500-4,000 करोड़ से ज्यादा एकत्र किए होंगे. उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने वैट को कम नहीं किया, उन्होंने हजारों करोड़ में अतिरिक्त राजस्व कमाया.

सावधान रहें! नए वैरिएंट बिगाड़ सकते हैं हालात, मुख्यमंत्रियों से बैठक में बोले पीएम नरेंद्र मोदी

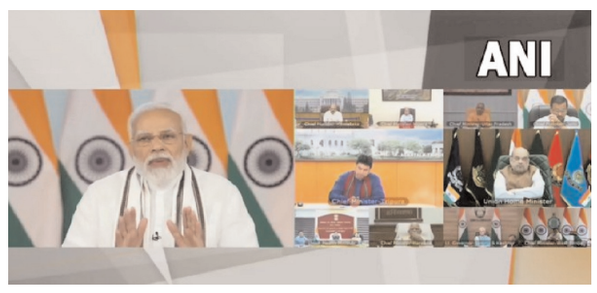

प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोरोना महामारी की ताजा स्थिति की समीक्षा के बाद अपने संबोधन में यह बात कही।

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पिछले दो हफ्तों में कुछ राज्यों में जिस प्रकार से कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़े हैं। उससे स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है, लिहाजा देशवासियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कोरोना महामारी की ताजा स्थिति की समीक्षा के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। उन्होंने कहा, जिस तरह से पिछले दो हफ्तों में कुछ राज्यों में मामले बढ़े हैं उससे ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह टली नहीं है। ओमीक्रोन और उसके सब वैरिएंट्स किस तरह गम्भीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, यह यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में कोरोना के विभिन्न स्वरूपों की वजह से कुछ लहरें भी आई, लेकिन भारत ने कई देशों की तुलना में हालात पर काफी बेहतर नियंत्रण रखा है। उन्होंने कहा, इन सब के बावजूद पिछले दो हफ्ते से जिस तरह से कुछ राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, उससे हमें सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2,927 नए मामले आए। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,65,496 हो गई।

पीएम की अपील पर कांग्रेस का हमला

नई दिल्ली । मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों से तेल पर वैट घटाने की अपील के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से केंद्र ने 26 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं। इस बात का जिक्र पीएम ने क्यों नहीं किया? पवन खेड़ा ने कहा कि आपने राज्यों को समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया और फिर अब आप राज्यों से वैट को कम करने के लिए कह रहे हैं। पहले उन्हें केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए, इसके बाद राज्यों से वैट कम करने के लिए कहना चाहिए।

कई कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार, लॉ यूनिवर्सिटीज, पूर्व जजों-आईएएस से मांगे सुझाव

नई दिल्ली ।

मोदी सरकार देश में बड़े कानून बदलाव की तैयारी कर रही है. इसके लिए सरकार ने नामी लॉ यूनिवर्सिटीज, सांसदों, कानूनविदों और पूर्व जजों से सुझाव मांगे हैं. सुझाव मिलने के बाद सरकार कानूनों में बड़े बदलाव करेगी. जानकारी के मुताबिक, पहले चरण में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव किए जाएंगे. केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, गृह मंत्रालय ने इसे लेकर सुझाव मांगे हैं, क्योंकि बहुत से कानून अब अप्रासंगिक हो चुके हैं.

जबकि बहुत से नए नेचर के मामले आ चुके हैं, जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट, डीएनए टेस्ट आदि की धाराएं नहीं हैं. इसलिए गृहमंत्री अमित शाह ने देश की नामी लॉ यूनिवर्सिटी, कानूनविद, सांसदों, पूर्व आईपीएस अधिकारियों और पूर्व जजों से सुझाव मांगे हैं. इन सबके बीच एसपी सिंह बघेल ने कहा कि इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना-देना नहीं है.

आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई के लिए गठित बेंच से जस्टिस राजीव सिंह ने खुद को अलग किया

नई दिल्ली । लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में रविवार (24 अप्रैल 2022) को सरेंडर करने वाले यूपी के गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के केस में नया मोड़ आ गया है। आशीष की जमानत पर बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश राजीव सिंह ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है। न्यायमूर्ति सिंह की बेंच ने ही पहले आशीष को जमानत दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को रद्द कर दिया था। प्रकरण की सुनवाई के लिए नए न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद अदालत मामले की अगली सुनवाई करेगी। मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच में 27 अप्रैल को होनी थी लेकिन उसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। जस्टिस राजीव सिंह ने खुद को मामले से अलग करने की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को दे दी है। अब मुख्य न्यायाधीश नयी बेंच का गठन करेंगे और तय करेंगे कि मामले की अगली सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाईकोर्ट की दी हुई जमानत रद्द करने के बाद 24 अप्रैल को आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 25 अप्रैल तक सरेंडर करने के आदेश दिए थे, लेकिन उसने एक दिन पहले ही सरेंडर कर दिया था। जिसके बाद आशीष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जमानत के लिए याचिका डाली थी, जिस पर 27 अप्रैल को सुनवाई होनी थी।

'हेट इन इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' साथ-साथ नहीं चल सकते : राहुल

नयी दिल्ली।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ वैश्विक ब्रांड के भारत छोड़ने की खबर का हवाला देते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि 'हेट इन इंडिया' (भारत में घृणा) और 'मेक इन इंडिया' (भारत में विनिर्माण) साथ-साथ नहीं चल सकते। उन्होंने देश में बेरोजगारी की स्थिति का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह इस संकट से निपटने पर ध्यान दें। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ''कारोबार भारत से बाहर ले जाने की सुगमता है। सात वैश्विक ब्रांड, नौ फैक्ट्रियां और 649 डीलरशिप चले गए। 84,000 नौकरियां खत्म हो गईं।'' उन्होंने कहा, ''मोदी जी, 'हेट इन इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' साथ-साथ नहीं चल सकते। भारत के खतरनाक बेरोजगारी संकट पर ध्यान देने का समय है।

तमिलनाडु : रथयात्रा के दौरान करंट लगने से 11 की मौत; पीएम, सीएम ने की वित्तीय सहायता की घोषणा

तंजावुर ।

तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक मंदिर में आज सुबह रथ जुलूस के दौरान करंट लगने से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि यह घटना उस समय हुई जब लोग जिस मंदिर की पालकी पर खड़े थे, वह कालीमेडु के अप्पर मंदिर में एक हाई-ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में आ गई।

अधिकारियों ने कहा कि मारे गए लोगों में दो बच्चे थे। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिरुचिरापल्ली के मध्य क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक वी बालकृष्णन ने कहा, हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए आम तौर पर मंदिर कार मार्ग पर बिजली लाइन बंद कर दी जाती है। अधिकारी ने कहा, हालांकि, पालकी इतनी लंबी नहीं थी कि हाई-ट्रांसमिशन लाइन को छू सके, और इस तरह इस बार बिजली की सप्लाई बंद नहीं की गई। लेकिन ऐसा लगता है कि सजावटी संरचना के चलते पालकी की ऊंचाई बढ़ा दी गई थी, और परिणामस्वरूप, यह लाइव वायर के संपर्क में आ गई। घटना के एक वीडियो में देखा जा सकता है कि लाइव वायर के संपर्क में आने से रथ पूरी तरह से नष्ट हो गया। गौरतलब है कि हर साल तमिलनाडु में वार्षिक रथ उत्सव में बड़ी संख्या में भक्त भाग लेते हैं। इस दुखद हादसे के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने वित्तीय सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि घटना में मारे गए 11 लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी परिजनों को वित्तीय सहायता की घोषणा की है। पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए PMNRF से 2-2 लाख रुपये की घोषणा की। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

किसी अन्य देश की हल्की प्रतिच्छाया नहीं बन सकते यूक्रेन संकट पर भारतीय रुख पर बोले जयशंकर

एस. जयशंकर ने कहा कि भारत को अपना रास्ता चुनने के लिए किसी अन्य देश की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है.

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत को अपना रास्ता चुनने के लिए किसी भी अन्य देश की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है. विदेश मंत्री का यह बयान रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर सख्त रूख अपनाने के लिए पश्चिमी देशों के भारी दबाव के बीच भारत की गुट-निरपेक्ष विदेश नीति की पुष्टि करता है. जयशंकर ने कहा कि भारत किसी भी अन्य देश को खुश करने के लिए उसकी हल्की प्रतिच्छाया नहीं बन सकता है. नई दिल्ली में जारी नेताओं और नीतिनिर्माताओं की अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी रायसीना डायलॉग के दौरान विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने कहा, हमें अपने रुख पर भरोसा रखना होगा... मुझे लगता है, दुनिया के साथ हमारा उसी तरह पेश आना बेहतर होगा, जैसे हम हैं, न कि कोशिश करके उनकी हल्की प्रतिच्छाया बन जाएं. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह सोचना कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहेंगे, यह सोचना कि हमें दूसरों से मंजूरी लेनी होगी, मुझे लगता है, उस युग को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए. मंगलवार को विदेशमंत्री ने यूक्रेन संकट को लेकर यूरोपीय देशों के विदेशमंत्रियों के सवालों के जवाब दिए थे, और पूछा था कि उस वक्त यूरोप कहां था, जब अफगानिस्तान जैसे एशियाई देश संकट में थे. यूरोपीय देशों पर अफगान जनता को संकट में धकेल देने का आरोप लगाते हुए जयशंकर ने यूरोपीय नेताओं को याद दिलाया कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बड़ी समस्याएं हैं. विदेशमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय माहौल का अपने पक्ष में इस्तेमाल करने तथा अतीत में की गई गलतियों को ठीक करने को लेकर भारत को प्रैक्टिकल होना चाहिए, तथा सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा, अगर हमने कोई एक उपलब्धि चुननी हो, जो पिछले 75 वर्षों के दौरान हमने किया हो, दुनिया को दिया हो, तो वह यह सच्चाई है कि हम लोकतंत्र हैं... विदेशमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र ही भविष्य है, और ऐसा भारत में अतीत में किए गए फैसलों की वजह से है. उन्होंने कहा, एक वक्त था, जब दुनिया के इस हिस्से में सिर्फ हम ही एकमात्र लोकतंत्र थे... अगर आज लोकतंत्र दुनियाभर में फैला है, तो कुछ हद तक इसका श्रेय भारत को जाता है.

1992 जैसे दंगे भड़काने के लिए अंडरवर्ल्ड से मिला था पैसा, संजय राउत का राणा दंपति पर निशाना

मुंबई। अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा पर दाऊद इब्राहिम के साथी यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपये का कर्ज मिलने का दावा करने वाले संजय राउत ने फिर राणा दंपति पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फंड का इस्तेमाल 1992 जैसा माहौल बनाने के लिए किया गया था। बताते चलें कि सितंबर 2021 में आर्थर रोड जेल में मारे गए लकड़ावाला को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। संजय राउत ने कहा, 1992 के दंगों की तरह, महाराष्ट्र में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिशों का अंडरवर्ल्ड से संबंध है। पुलिस और सरकार देख सकती है कि हनुमान चालीसा पंक्ति और लाउडस्पीकर सहित पिछले 15 दिनों के घटनाक्रम को 1992-93 के दंगों से पहले जैसा माहौल बनाने के लिए उकसाया गया था। ईडी की कार्रवाई का सामना करने वाले शिवसेना सांसद ने 80 लाख रुपये के लेन-देन की जांच नहीं करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी से सवाल किया। उन्होंने कहा, अगर लकड़ावाला ने 200 करोड़ की लूट की, तो राणा दंपत्ति एक निश्चित लाभार्थी थे। उन्होंने आगे कहा, अगर लकड़ावाला के खाते से नवनीत के खाते में 80 लाख जमा किए गए, तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई? मेरा सवाल ईडी से है। 20 लाख- 25 लाख के लिए, आप हमारे मंत्रियों को सलाखों के पीछे डालते हैं, आप हमारी संपत्तियां कुर्क करते हैं। फिर लकड़ावाला के लिए, जो 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आपकी हिरासत में था, आपने उन सभी को बुलाया, जिनका उसके साथ वित्तीय लेन-देन था तो राणा दंपत्ति इस पूछताछ से क्यों बच गए?

स्पीकर को लिखूंगा खत- राउत

राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अंडरवर्ल्ड से उनके कथित संबंधों के बारे में पत्र लिखेंगे।

एसडीएमसी का बुलडोजर तैयार

दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी

नई दिल्ली।

देश की राजधानी में दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। आने वाले दिनों दक्षिण दिल्ली नगर निगम अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इसके लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की एक टीम तीन वार्डों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने से पहले क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए बुधवार को दिल्ली के जैतपुर पहुंची। इसमें दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से पहले जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर इलाके का निरीक्षण कर रही है, जिसके बाद कार्रवाई की तारीख तय की जाएगी।

अतिक्रमण अभियान के खिलाफ कार्रवाई से पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर और कमिश्नर बुधवार को जैतपुर सरिता विहार और मदनपुर खादर क्षेत्र में अतिक्रमण व अवैध निर्माण का निरीक्षण किया।

बता दें कि शाहीन बाग में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है, जहां पर सीएए-एनआरसी के खिलाफ लंबा आंदोलन चला था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भले ही दिल्ली नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भले ही रुक गया है, लेकिन अन्य इलाकों में जारी है।

मिली जानकारी के मुताबिक, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कई जगहों पर आगामी 1 महीने का अतिक्रमण विरोधी अभियान जल्द शुरू करेगा। वहीं, अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे नगर निगमों के अभियान ने जोर पकड़ लिया। मंगलवार को उत्तरी और दक्षिणी निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की। अस्थायी अतिक्रमण और फुटपाथ पर किए गए कब्जों को हटाया। निगम की टीम ने सामान भी जब्त कर लिया।

उत्तराखंड में 'हिंदू महापंचायत' को रोकने के लिए धारा 144 लागू, 33 लोग हिरासत में लिए गए

देहरादून। उत्तराखंड के रुड़की के निकट डाडा जलालपुर गांव में 'हिंदू महापंचायत' को रोकने के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है और कार्यक्रम से जुड़े 33 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह कार्यक्रम कल यानी बुधवार को होना था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। डाडा जलालपुर गांव में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गयी शोभायात्रा पर पथराव के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। निषेधाज्ञा लागू करने का कदम तब उठाया गया जब एक दिन पहले मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह अदालत में सार्वजनिक रूप से यह कहें कि रुड़की में निर्धारित 'धर्म संसद' में कोई अप्रिय बयान नहीं दिया जाएगा और चेतावनी दी कि अगर कोई घृणा भाषण दिया जाएगा तो वह शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगा।

एलआईसी आईपीओ : बाजार को सुरक्षा देने के लिए घटाया आकार, इन्फोसिस के बाद बन सकती है 5वीं बड़ी कंपनी

नई दिल्ली।

सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आईपीओ का आकार घटा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह शेयर बाजार को स्थिर रखना और विदेशी निवेशकों के घरेलू बाजार से पलायन को रोकना है। इसके अलावा, सरकार पहले जानना चाहती है कि इसका वास्तविक मूल्य क्या होना चाहिए। छोटे इश्यू से यह भी पता चलेगा कि निवेशकों का इसमें कितना रुझान है। इन वजहों से मर्चेंट बैंकर्स ने एलआईसी का वैल्यूएशन और भाव कम कर दिया है। आईपीओ का भाव 902-949 रुपये तय किया गया है, जिसके पहले 1,800 रुपये पर लाने का अनुमान था। वैल्यूएशन के मोर्चे पर एक लाख करोड़ की जगह अब 21,000 करोड़ जुटाए जाएंगे। इसके साथ ही एलआईसी बाजार पूंजी के लिहाज से इन्फोसिस के बाद 5वीं सबसे बड़ी कंपनी होगी। पहले आरआईएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनने का अनुमान था अर्थशास्त्री डॉ. अरुण कुमार कहते हैं कि शेयर बाजार में निवेश करने वाले कभी भी बाजार से ही पैसा निकाल कर वापस उसमें लगाते हैं। कोई जमा पैसा हर बार बाजार में नहीं लगाता हो। सरकार अगर एक लाख करोड़ रुपये का एलआईसी का आईपीओ लाती तो इसी आधार पर निवेशक भी शेयर बाजार से पैसे निकालकर उसमें लगाते। इससे बाजार में अस्थिरता का माहौल बन जाता। डॉ. कुमार का

कहना है कि विदेशी निवेशक इस समय घरेलू बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। उनका वापस आना मुश्किल है। रूस-यूक्रेन की वजह से माहौल खराब है। ऐसे में सरकार छोटे आईपीओ के जरिये बाजार का माहौल देखना चाहती है। इसके बाद सरकार दूसरे चरण में इसकी ज्यादा हिस्सेदारी बेच सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कहते हैं कि अनिश्चितता भरे माहौल में आकार को कम कर दिया गया है। हालांकि, सरकार विनिवेश जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार इसी साल या अगले साल एक बार फिर से एफपीओ के जरिये एलआईसी में हिस्सेदारी बेच सकती है। माना जा रहा है कि जब माहौल सुधरेगा तो सरकार एक अच्छी कीमत पर ज्यादा हिस्सेदारी बेचने की योजना बना सकती है। 4 मई को आने वाले आईपीओ में पॉलिसीधारकों को 60 रुपये प्रति शेयर की छूट मिल सकती है, जबकि खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों को 40 रुपये की छूट मिलने का अनुमान है। कुल 22.1 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे। माना जा रहा है कि आईपीओ 2 मई को एंकर निवेशकों के लिए खुल सकता है। बोलियां 15 शेयरों के लॉट में लगाई जाएंगी। पिछले साल 28 मार्च को मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमणियन ने कहा था कि सरकार एलआईसी में हिस्सेदारी बेचकर एक लाख करोड़ जुटा सकती है। अब यह 21,000 करोड़ हो गया है। एक साल में यह 80त्न घट गया है। किसी भी आईपीओ का भाव तय करने में मर्चेंट बैंकर्स की भूमिका होती है। वे निवेशकों से राय लेकर भाव तय करते हैं। एलआईसी के पूर्व अधिकारी ने बताया, बाजार के खराब माहौल में भी आईपीओ आते हैं और अच्छा रिस्पांस मिलता है। लेकिन, जिस तरह से पहले से ही एलआईसी के वैल्यूएशन और जुटाई जाने वाली रकम को लेकर हल्ला मचाया गया, उससे अब मामला फंस गया है।

एक नजर

सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत भी गिरी

नई दिल्ली । आज आभूषण खरीदने का मन बना रहे हैं तो अच्छा मौका है। दरअसल, दोनों कीमती धातुओं के भाव में गिरावट आई है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को एमसीएक्स पर जहां सोने की कीमत 0.14 फीसदी कम होकर 51,511 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई, जबकि चांदी के दाम में मामूली 0.04 फीसदी की गिरावट आई और इसका भाव कम होकर 64,941 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया है। देश भर में सोने के आभूषणों की कीमत उत्पाद शुल्क, राज्य करों और मेकिंग चार्ज के कारण बदलती रहती है। आप अपने शहर सोने की कीमत मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आप सिर्फ 8955664433 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर प्राइस चेक कर सकते हैं। आप जिस नंबर से मैसेज करते हैं उसी नंबर पर आपके मैसेज आ जाएगा। इस तरह आप घर बैठे सोने के लेटेस्ट रेट जान लेंगे। यहां बता दें कि आभूषण बनाने के लिए ज्यादातर 22 कैरेट का ही इस्तेमाल होता है। कुछ लोग 18 कैरेट सोने का भी इस्तेमाल करते हैं। आभूषण पर कैरेट के हिसाब से हॉल मार्क बना होता है। 24 कैरेट सोने के आभूषण पर 999 लिखा होता है, जबकि 23 कैरेट पर 958, 22 कैरेट पर 916, 21 कैरेट पर 875 और 18 कैरेट पर 750 लिखा होता है।

तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल-डीजल के दाम

नई दिल्ली ।

तेल कंपनियों की तरफ से आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 105.41 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120.51 रुपये व डीजल की कीमत 104.77 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 115.12 रुपये जबकि डीजल का दाम 99.83 रुपये प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 110.85 रुपये प्रति लीटर तो डीजल 100.94 रुपये प्रति लीटर है। बता दें कि पिछले वर्ष 4 नवंबर के बाद से इन दोनों ईंधन के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। सरकार के राजनीतिक विरोधियों का आरोप था कि पांच राज्यों के चुनाव के कारण मोदी सरकार ने तेल कंपनियों को

मूल्य बढ़ाने से रोक रखा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 112 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने के बाद रविवार को तेल कंपनियों ने डीजल के थोक खरीदारों के लिए मूल्य में 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। तेल डीलरों का कहना है कि खुदरा मूल्य में धीरे-धीरे वृद्धि की जाएगी। बता दें कि मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपये से ऊपर चल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे अधिक है। पेट्रोल-डीजल की कीमत आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर आपको अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग-अलग है, जो आपको आईओसीएल की वेबसाइट से मिल जाएगा। बता दें कि प्रतिदिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में यह कॉस्ट भी जुड़ती है।

निवेश का आमंत्रण: अमेरिकी सेमीकंडक्टर को भारत में मिलेगा प्रोत्साहन, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की उद्योग जगत से मुलाकात

वाशिंगटन। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर उद्योग के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें भारत में निवेश का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कंपनियों को प्रोत्साहन का फायदा दिया जाएगा। सिलिकॉन वैली में स्थित कंपनियों के अधिकारियों को उन्होंने भारत में तमाम अवसरों की जानकारी दी और कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत सरकार एक बड़े मिशन को लेकर चल रही है। सरकार ने पिछले साल देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत को उच्च प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादन के प्रमुख के रूप में स्थापित करना है। भारत चिप उद्योग को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन की नीति को बढ़ावा दे रहा है। वित्तमंत्री ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र की दिग्गज हस्तियों के साथ बैठक में कहा कि भारत ने हाल के समय में अपनी क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ाया है। रिसर्च एवं विकास के लिए अकादमिक संस्थानों के साथ सहयोग भी कर रहे हैं। वित्तमंत्रालय ने इस बारे में एक ट्वीट किया और कहा कि वैश्विक आपूर्ति चेन में अड़चनों के कारण कुछ क्षेत्रों पर ज्यादा निर्भरता की समीक्षा की जा रही है। वित्तमंत्री ने भारत में उबर की विस्तार योजना की जानकारी देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी कंपनियां यातायात को मजबूत बनाने और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला, सेंसेक्स 430 अंक फिसला, निफ्टी 17100 से नीचे

नई दिल्ली । कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 430 अंक या 0.75 फीसदी टूटकर 56,926 के स्तर पर खुला, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने 116 अंक या 0.67 फीसदी फिसलकर 17,085 के स्तर पर शुरुआत की। बाजार खुलने के साथ ही लगभग 772 शेयरों में तेजी आई, 1203 शेयरों में गिरावट आई और 114 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर अडानी पोर्ट्स, ओएनजीसी, एचडीएफसी लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल्स और सन फार्मा प्रमुख लाभ वाले शेयरों में थे, जबकि बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, बजाज फिनसर्व, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और इंफोसिस के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले बीते कारोबारी सत्र मंगलवार को शेयर बाजार जोरदार बढ़त के साथ बंद हुआ था। बीएसई का सेंसेक्स सूचकांक 777 अंक या 1.37 फीसदी की तेजी लेते हुए 57,357 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि एनएसई का निफ्टी सूचकांक 247 अंक या 1.46 फीसदी की उछाल के साथ 17,201 के स्तर पर बंद हुआ था।

अनुमान: इस महीने रिकॉर्ड तोड़ सकता है जीएसटी संग्रह 1.45 से 1.50 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद

मुंबई। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह इस महीने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उम्मीद है कि 1.45 से 1.50 लाख करोड़ रुपये इसके जरिये सरकार को मिल सकता है। मार्च में अब तक का सबसे ज्यादा 1.42 लाख करोड़ रुपये का टैक्स मिला था। अप्रैल 2021 में सरकार को 1.41 लाख करोड़ रुपये मिले थे, जो दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। वित्त मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि मासिक आधार पर इस बार ज्यादा ई-वे बिल बने हैं, जिनके कारण टैक्स में बढ़ोतरी होगी। अगर अप्रैल में 1.45 लाख करोड़ रुपये सरकार को मिलते हैं तो यह लगातार दसवां महीना होगा, जिसमें एक लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स मिलेगा। जुलाई, 2021 से लेकर अब तक हर महीने एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स मिला है। मासिक आधार पर सबसे ज्यादा बढ़त 33 फीसदी जुलाई महीने में ही हुई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीएसटी के तहत कुल 14.83 लाख करोड़ रुपये मिले थे। यह 2020-21 में मिले 11.37 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 30 फीसदी ज्यादा था। माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार और चोरी पर लगाम लगने की वजह से टैक्स वसूली में बढ़त हो रही है। वित्त मंत्रालय ने 25 अप्रैल को कहा था कि मंत्रियों का एक समूह टैक्स की दरों को लेकर अभी भी रिपोर्ट नहीं सौंपा है। पिछले साल इस समूह को बनाया गया था। इसके मुताबिक, टैक्स की दरों में संशोधन किया जाना है।

अगले दो साल में बड़ी संख्या में नौकरी छोड़ सकती हैं महिलाएं

नई दिल्ली ।

अगले दो साल में काम का दबाव या अत्यधिक काम का बोझ (बर्नआउट), कार्य घंटों में लचीलेपन की कमी की वजह से बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के बीच बड़ी संख्या में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। विशेष रूप से महिला कर्मचारियों द्वारा लगातार नौकरी छोड़ने का सिलसिला जारी है। डेलॉयट की महिलाएंञ्चकार्य-2022 एक वैश्विक परिदृश्य रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 56 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि एक साल पहले की तुलना में उनके तनाव का स्तर ऊंचा था और करीब आधी महिलाएं काम के बोझ की वजह से थकावट महसूस कर रही हैं। यह रिपोर्ट

नवंबर, 2021 से फरवरी, 2022 के बीच 10 देशों में सर्वे पर आधारित है। इसमें 5,000 महिलाओं के विचार लिए गए। इनमें से 500 महिलाएं भारत की हैं। सर्वेक्षण में शामिल आधी से ज्यादा महिलाएं अगले दो वर्षों में अपने नियोक्ता को छोड़ना चाहती हैं। इनमें से केवल नौ प्रतिशत महिलाओं ने ही अपने वर्तमान नियोक्ता के साथ पांच साल से अधिक समय तक काम करने की योजना बनाई है। बर्नआउट यानी काम का बोझ प्रमुख वजह है जिसकी वजह से महिलाएं नौकरियां बदलना चाहती हैं। करीब 40 प्रतिशत ने कहा कि वे सक्रिय रूप से नई कंपनी की तलाश कर रही हैं। रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि अधिकांश महिलाओं ने काम के दौरान गैर-समावेशी व्यवहार की बात कही। हालांकि, ज्यादातर ने नियोक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक, एक साल पहले की भावनाओं की तुलना में कई महिलाएं अपने करियर की संभावनाओं के बारे में कम आशान्वित महसूस करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हाइब्रिड कार्य वातावरण में काम करने वाली लगभग 60 प्रतिशत महिलाओं को लगता है कि उन्हें महत्वपूर्ण बैठकों से बाहर रखा जाता है। डेलॉयट इंडिया के भागीदार और विविधता, समानता और समावेशन प्रमुख मोहनीश सिन्हा ने कहा, हाइब्रिड मॉडल को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य के रूप में देखा गया है, जिससे लोगों को घर से और कार्यालय से काम करने की सुविधा मिलती है। सर्वे से हमें पता चला है कि महिला पेशेवरों को दोनों ही स्थितियों में नुकसान हो रहा है। साल-दर-साल उनकी देखभाल की जिम्मेदारियों के साथ तनाव भी बढ़ रहा है।

अच्छी खबर: भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 14 लाख करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली । भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, इस बार भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीबीडीटी प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.09 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया यानी इसमें 49.02 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जेबी महापात्र ने बताया कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में वापसी के संकेत हैं। महापात्र ने एक सम्मेलन के अंत में कहा कि 2021-22 का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (आई-टी रिफंड को ध्यान में रखते हुए) 2018-19 में हासिल किए गए 11.37 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ अधिक है। जेबी महापात्र ने कहा कि 2021-22 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.75फीसदी से अधिक की वृद्धि दिखाते हुए, 16.34 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया। जेबी महापात्र ने कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर 2021-22 के लिए 7.14 करोड़ से अधिक I-T रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि 2020-21 के लिए 6.97 करोड़ से अधिक दाखिल किए गए थे। महापात्र ने कहा कि पहली बार प्रत्यक्ष कर संग्रह ने अप्रत्यक्ष कर संग्रह को पछाड़ दिया है, जो कुल कर संग्रह का 52 फीसदी है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ सालों में इसे 60 फीसदी करने का लक्ष्य है और अगले 15 सालों में टैक्स-जीडीपी अनुपात को मौजूदा 12 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी करना है।

ट्विटर पर 'बोलने की आजादी' का मस्क का विचार क्या असर दिखाएगा

वाशिंगटन। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद रहे हैं और इसके पीछे उन्होंने इस मंच को 'बोलने की स्वतंत्रता' का स्थान बनाने का उद्देश्य बताया है। हालांकि यह सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहले भी इस रास्ते से गुजर चुका है लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। ट्विटर के एक पदाधिकारी ने एक दशक पहले अभिव्यक्ति की अदम्य स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कंपनी को 'बोलने की आजादी वाली पार्टी की बोलने की आजादी वाली शाखा' करार दिया था। लेकिन बाद के घटनाक्रमों से 'बोलने की आजादी' वाले दावे को लेकर परीक्षा की घड़ी आ गयी जब दमनकारी शासकों ने ट्विटर के उपयोगकर्ताओं पर कार्रवाई शुरू की और खासतौर पर 'अरब स्प्रिंग' के मद्देनजर ऐसे मामले सामने आये। अमेरिका में 2014 में पत्रकार अमांडा हेस के एक विचारोत्तेजक लेख ने ट्विटर या अन्य ऑनलाइन मंचों पर पोस्ट डालने मात्र के लिए अनेक महिलाओं को सहने पड़े उत्पीड़न को उजागर किया गया। साल दर साल ट्विटर ने व्यापक रूप से एक अनियंत्रित सामाजिक मंच को चलाने के परिणामों को लेकर कुछ चीजें समझीं।

इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी कि कपनियां आमतौर पर हिंसक धमकियों, नफरत भरे भाषणों जैसी विषयवस्तु के साथ अपने विज्ञापन नहीं चलाना चाहतीं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स में उप निदेशक पॉल बारेट ने कहा, ''यदि आप स्वचालित प्रणालियों और मानवीय समीक्षाओं पर नियंत्रण बंद कर देंगे तो ट्विटर जैसी साइट बहुत कम समय में कूड़ाघर हो जाएगी।'' बारेट ने बताया कि किस तरह गूगल ने इस बात को बहुत जल्द समझ लिया था जब टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों ने 2015 में उग्रवादियों के यूट्यूब वीडियो से पहले अपने विज्ञापन चलाये जाने पर उन्हें वापस ले लिया था।

ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने भी इस मंच पर विचारों के आदान-प्रदान को सुधारने के लिए सालों काम किया था। बड़ा सवाल है कि खुद को स्वतंत्र भाषण का हिमायती बताने वाले मस्क इस दिशा में कितना काम कर पाते हैं।

कृषि आय बढ़ाने के लिए बीजों के साथ प्रयोग और प्रौद्योगिकी का उपयोग जरूरी: कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से उत्पादन और आय बढ़ाने के लिए प्रयोग करने, नई बीज किस्मों को अपनाने, नई तकनीकों का उपयोग करने और अपनी कृषि भूमि की गुणवत्ता का परीक्षण कराने का आग्रह किया है। तोमर ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 25-30 अप्रैल, 2022 के दौरान आयोजित होने वाले किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी अभियान की शुरुआत करते हुए यह बात कही। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, तोमर ने देश भर के कई राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में मौजूद किसानों से बातचीत की। बातचीत का उद्देश्य किसानों को सरकार की प्रमुख योजनाओं से अवगत कराना और जमीनी स्तर पर किसानों को मिलने वाले लाभों का आकलन करना था। किसानों के साथ बातचीत करते हुए, तोमर ने कृषि क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि इस बात का उदाहरण है कि कैसे प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता

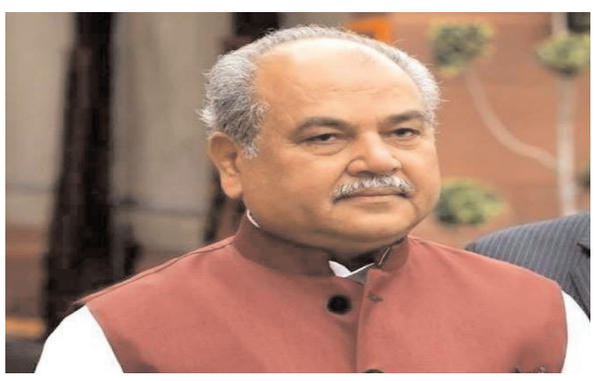

सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी को अपनाना, फसलों का विविधीकरण और निर्यात बाजार में गुणवत्ता बनाए रखना आवश्यक है। मंत्री ने किसानों से कहा कि उन्हें समय के साथ प्रयोग करने और बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, उन्हें नई किस्म के बीजों का उपयोग करने, अपनी मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण करने, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में शामिल होने और ड्रोन सहित नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तोमर ने कहा कि केवीके और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) विकसित प्रौद्योगिकियों को कृषक समुदाय तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के सुरक्षा कवच को अपनाना चाहिए। वहीं, प्राकृतिक खेती पर मंत्री ने कहा कि इसे बढ़ावा दिया जा रहा है और कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर रहा है।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों को एफडी सुविधा देने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ गठजोड़ किया

नयी दिल्ली। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मियादी जमा (एफडी) सुविधा शुरू करने के लिए इंडसइंड बैंक से हाथ मिलाया है। इसके तहत एफडी पर बैंक 6.5 प्रतिशत का ब्याज देगा। परिपक्वता से पहले एफडी को तोड़ने पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। बैंक ने यह जानकारी दी। इंडसइंड बैंक ने एक बयान में कहा कि एफडी सुविधा की शुरुआत के साथ ही एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है। विज्ञप्ति में कहा गया कि ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से 500 रुपये से 1,90,000 रुपये तक की राशि को जमा कर सकते हैं। उन्हें इसपर सालाना 6.5 प्रतिशत तक का ब्याज दिया जाएगा। सभी मियादी जमाओं पर वरिष्ठ नागरिकों को 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। बैंक ने विज्ञप्ति में कहा, ''ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से एफडी की समय अवधि पूरी होने से पहले उसे तोड़ सकते हैं और इसके लिए उनसे कोई जुर्माना या प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा।'' इंडसइंड बैंक ने कहा कि एफडी सुविधा एक, दो या तीन साल की निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध होगी। ग्राहक एक समय में कई एफडी कर सकते हैं।

एक नजर

दिल्ली के बवाना में दो लोगों की सीवर में गिरने से मौत

दिल्ली । राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में बालाजी चौक के पास दो लोगों की सीवर में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। सूचना पर दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों का नाम चितरंजन और अब्दुल कलाम बताया जा रहा है। दमकल विभाग के एक अधिकार ने बताया कि बुधवार सुबह 11:25 बजे बवाना इलाके में बालाजी चौक पर गंगा टोली मंदिर के पास बचाव के बारे में एक कॉल प्राप्त हुई जिसके बाद तुरंत दो दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया। यहां पहुंचे ही बचावा टीम ने सीवर में गिरे दो लोगों को बाहर निकाला और घायल अवस्था में उन्हें महर्षि बाल्मीकि अस्पताल भेजा गया। यहां पर डॉक्टरों ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया। इससे पहले, बीते 29 मार्च को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में सीवर से गुजर रही टेलीफोन केबल की मरम्मत करने उसते तीन मजदूरों समेत चार लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में दो मजदूर थे जो एमटीएनएल के कॉन्ट्रैक्ट पर सीवर लाइन में तार बिछाने का काम कर रहे थे। वहीं, एक ठेकेदार सुरेश और एक रिक्शा चालक सतीश था जो घटना के वक्त वहीं मौजूद था। जानकारी के अनुसार, जब मजदूर सीवर लाइन के अंदर फंस गए तो सतीश इनकी आवाज सुनकर उनको बचाने के लिए आया और वह भी इस हादसे का शिकार बन गया।

भलस्वा लैंडफिल पर लगी आग पर काबू, धुएं से ढका पूरा इलाका

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के भलस्वा लैंडफिल साइट के डंप यार्ड में मंगलवार शाम लगी रात को लगी आग पर काबू तो पा लिया गया। लेकिन बुधवार सुबह पूरे इलाके में इसका धुआं फैला नजर आया। बुधवार सुबह तक घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां मौजूद रही लेकिन धुएं के कारण स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इलाके में प्रदूषण को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली में भलस्वा डंप यार्ड के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने कहा, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं और ना ठीक से देख पा रहे हैं। सरकार को यहां डंप यार्ड की स्थिति पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि मंगलवार को अधिकारियों ने बताया कि दमकल विभाग को शाम करीब 5:47 बजे भलस्वा लैंडफिल साइट पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 10 दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और धुएं से लोगों भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। गौरतलब है कि इस साल पूर्वी दिल्ली स्थित गाजीपुर लैंडफिल स्थल पर आग लगने की तीन घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 28 मार्च को लगी आग को बुझाने में 50 घंटे से अधिक तक मशक्कत करनी पड़ी थी।

26 मई को मोदी सरकार के हो जाएंगे पूरे 8 साल, मेगा तैयारी में जुटी बीजेपी

नई दिल्ली । केंद्र की सत्ता में 8 साल पूरे होने पर बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है. 26 मई को मोदी सरकार को 8 साल पूरे हो जाएंगे जिसको खास बनाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महासचिवों के साथ मिलकर योजना तैयार करने में जुटे हैं. जानकारी के मुताबिक, बीजेपी पूरे देशभर में भव्य कार्यक्रम की योजना बना रही है. बताया जा रहा है कि, दो दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार के मई में 8 साल पूरे होने पर पूरे देश में भव्य कार्यक्रम कराने का खाका खींचा गया. इस पूरे आयोजन के लिए एक टीम बनाई गई है जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के महासचिवों को शामिल किया गया है. ये टीम मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद होने वाले कार्यक्रमों को तय करेगी लेकिन इन कार्यक्रमों से देश में जनहित में और गरीब कल्याण योजनाओं के प्रति आम लोगों में जागरूकता पर खास फोकस किया जाएगा. इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी ने वीक बूथ कमेटी टीमों का गठन करने का भी प्लान बनाया है. इसके अंतर्गत जहां- जहां बीजेपी कमजोर स्थिति में है वहां ज़्यादा फोकस किया जाएगा और इसके लिए उस बूथ पर वीक बूथ कमेटी बनाई जाएगी. इस टीम में चार से पांच मेंबर रखे जाएंगे जो पार्टी को उस बूथ पर मजबूत करने के लिए काम करेंगे. इस तरह की टीम पूरे देश में बूथों के हिसाब से बनाई जाएंगी. सूत्रों की मानें तो इन बूथ कमेटी के कॉर्डीनेशन की ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयंत पांडा को दी गई है. इसके साथ ही बीजेपी महासचिव सीटी रवि, लाल सिंह आर्य, दिलीप घोष समेत कुछ और नेता भी इस टीम में शामिल किए गये हैं.

एक महिला समेत दो लोगों के शव नहर से बरामद, हत्या की आशंका

नोएडा ।नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में एक महिला समेत दो लोगों का शव नहर से बरामद किया गया है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि बीती रात को नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिला। उन्होंने बताया कि पुलिस आसपास के लोगों की सहायता से शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस को शक है कि महिला की हत्या कर शव को नहर में फेंका गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से इस बात की सूचना प्रसारित की। पुलिस आयुक्त आगे ने बताया कि नहर से एक अन्य शव भी मिला और मृतक की शिनाख्त बुधवार सुबह मुरादनगर निवासी अतुल शर्मा के रूप में हुई है। इस बाबत निवाड़ी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच, सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के छीजारसी कॉलोनी में रहने वाली एक महिला का शव बुधवार सुबह पंखे के फंदे से लटका हुआ मिला है। महिला के ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है जबकि उसके मायके वालों का आरोप है कि उसकी दहेज के लिए हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपर पुलिस उपायुक्त (द्वितीय जोन) ईलामारन ने बताया कि सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के छीजारसी कॉलोनी में रहने वाली सबा (19) का शव बुधवार सुबह उसके घर पर पंखे के फंदे से लटका हुआ मिला है। उन्होंने बताया कि मृतका के पति शादाब ने पुलिस को बताया है कि उसने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या की है। अधिकारी ने बताया कि मौके पर फॉरेंसिक टीम तथा मजिस्ट्रेट को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि महिला की दो माह पहले शादी हुई थी। उन्होंने बताया कि मृतका के परिजन को घटना की सूचना दे दी गई है। वहीं, मृतका के पिता इंतजार ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी की दहेज के लिए हत्या की गई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।

राजद्रोह कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को अंतिम सुनवाई, केंद्र से 4 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को राजद्रोह कानून की वैधता पर अंतिम सुनवाई करेगा. पिछले साल कोर्ट ने कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए केंद्र से जवाब मांगा था. आज केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जवाब तैयार है. 2 दिन में दाखिल कर दिया जाएगा. कोर्ट ने इसी हफ्ते जवाब दाखिल करने को करते हुए कहा कि 5 मई को सुनवाई नहीं टाली जाएगी. पूरा दिन मामला सुना जाएगा. आईपीसी की धारा 124 का मतलब है सेडिशन यानी कि राजद्रोह. अगर कोई अपने भाषण या लेख या दूसरे तरीकों से सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करता है तो उसे तीन साल तक की कैद हो सकती है. कुछ मामलों में ये सजा उम्रकैद तक हो सकती है. यहां ये साफ करना ज़रूरी है कि सरकार का मतलब संवैधानिक तरीकों से बनी सरकार से है, न कि सत्ता में बैठी पार्टी या नेता. भारत का संविधान बनाए जाते समय संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अंग्रेजों के ज़माने के इस कानून पर सवाल उठाए थे. इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ माना था. लेकिन उस वक़्त संविधान सभा अभिव्यक्ति के अधिकार को पूरी तरह से खुला छोड़ना सही नहीं माना. संविधान बनाने वालों ने अनुच्छेद 19 (2) के तहत इस अधिकार की सीमाएं तय कर दीं. इसके तहत भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुँचाने वाले बयान मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं माने गए. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने बाद में कई बार आईपीसी की धारा 124ए को हटाए जाने की वकालत की. इसे

अपना निजी विचार बताया. राजद्रोह पर 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था. केदारनाथ सिंह बनाम बिहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो इस धारा को बनाए रखा. उसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर देने से मना कर दिया. लेकिन इस धारा की सीमा तय कर दी. कोर्ट ने साफ कर दिया कि सिर्फ सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं माना जा सकता. जिस मामले में कुर्सी भाषण या लेख का मकसद सीधे सीधे सरकार या देश के प्रति हिंसा भड़काना हो, उसे ही इस धारा के तहत अपराध माना जा सकता है. बाद में 1995 में बलवंत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले लोगों को भी इस आधार पर छोड़ दिया था कि उन्होंने सिर्फ नारे लगाए थे. सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ मणिपुर के पत्रकार किशोरचन्द्र वांगखेमचा, छत्तीसगढ़ के पत्रकार कन्हैयालाल शुक्ला, सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल एस जी बोम्बतकरे, एडिटर्स गिल्ड सहित 8 याचिकाएं लंबित हैं. पिछले साल 15 जुलाई को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि इस कानून का उपयोग अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के खिलाफ किया था. आश्चर्य है कि आजादी के लगभग 75 साल बाद भी सरकार इस कानून को बनाए रखने की ज़रूरत समझती है. चीफ जस्टिस ने आगे कहा था, यह कानून ऐसा है जैसे किसी बढ़ई को लकड़ी का एक टुकड़ा काटने के लिए आरी दी गई और वह पूरा जंगल काटने लग गया. सरकार कई पुराने कानूनों को खत्म कर रही है. राजद्रोह कानून पर अब तक उसका ध्यान क्यों नहीं गया? सुनवाई के दौरान एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट की चिंता से सहमति जताते हुए कहा था, निश्चित रूप से इस कानून के दुरुपयोग पर रोक लगनी चाहिए. इसे सिर्फ देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सीधे आघात पहुंचाने के मामलों तक सीमित रखने की ज़रूरत है. केंद्र की तरफ से कोर्ट का नोटिस स्वीकार करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी संकेत दिए थे कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कदम उठाना चाहती है. मेहता ने कहा, सरकार की तरफ से जवाब दाखिल होने दीजिए. कोर्ट की बहुत सारी चिंताएं कम हो जाएंगी.

भारत के सहयोग से फिजी में बना दक्षिण प्रशांत क्षेत्र का पहला चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली । ओशिनिया महाद्वीप के देश फिजी में भारत के सहयोग से एक बच्चों का अस्पताल बना है। पीएम मोदी ने बुधवार को इसका उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फिजी के रिश्ते आपसी सम्मान और सहयोग पर टिके हैं तथा पिछले कुछ दशकों में दोनों के रिश्ते हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और मजबूत हुए हैं। फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हार्ट अस्पताल का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह उम्मीद जताई कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। इस अवसर पर फिजी के उनके समकक्ष फ्रेंक बेनीमरामा और साई प्रेम फाउंडेशन से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल दोनों देशों के पारस्परिक रिश्तों और प्रेम का एक और प्रतीक है तथा ये भारत और फिजी की साझा यात्रा का एक और अध्याय है। उन्होंने कहा, ''मुझे विश्वास है, ये हॉस्पिटल फिजी और इस पूरे क्षेत्र में सेवा का एक मजबूत अधिष्ठान बनेगा और भारत-फिजी

रिश्तों को नई ऊंचाई देगा।'' उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल न केवल फिजी में बल्कि पूरे दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में पहला चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल है। यह हमारे पारंपरिक संबंधों का प्रतीक है और भारत-फिजी की साझा यात्रा का एक और अध्याय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशाल समुद्र जरूर है लेकिन ''हमारी संस्कृति ने हमें एक दूसरे से जोड़कर'' रखा है। उन्होंने कहा, ''हमारे रिश्ते आपसी सम्मान, सहयोग और हमारे लोगों के मजबूत आपसी सम्बन्धों पर टिके हैं। बीते दशकों में भारत-फिजी के रिश्ते हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़े हैं और मजबूत हुए हैं। फिजी और प्रधानमंत्री बेनीमरामा के सहयोग से हमारे ये रिश्ते आने वाले समय और भी मजबूत होंगे।'' मोदी ने कहा कि मानव मात्र की सेवा और जीव मात्र का कल्याण यही भारत के संसाधनों का एक मात्र उद्देश्य है और इन्हीं मूल्यों पर भारत और फिजी की साझी विरासत खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इन्हीं आदर्शों पर चलते हुये कोरोना महामारी जैसे कठिन समय में भी भारत ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है। उन्होंने कहा, ''वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हुये भारत ने दुनिया के 150 देशों को दवाएं भेजीं, जरूरी सामान भेजा। अपने करोड़ों नागरिकों की चिंता के साथ साथ भारत ने दुनिया के अन्य देशों के लोगों की भी चिंता की। हमने करीब-करीब 100 देशों को 100 मिलियन के आसपास टीके भेजे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रयास में भारत ने फिजी को अपनी प्राथमिकता में रखा। उन्होंने इस अवसर पर सत्य साई बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते उनके कार्यों की सराहना की और कहा कि मानवता की सेवा के लिए उनके द्वारा रोपा गया बीज आज वटवृक्ष के रूप में लोगों की सेवा कर रहा है।

दिल्ली-एनसीआर में फिर शुरू हुआ भीषण गर्मी और लू का दौर, 1 मई तक घर से निकलें तो बरतें सावधानी

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में राहत का दौर अब खत्म हो चुका है। बुधवार सुबह से तेज धूप और गर्मी के बीच लू भी चलनी शुरू हो गई है। गर्म हवाओं ने दिल्ली-एनसीआर के लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और आने वाली 1 मई तक राहत के आसार नहीं है। वहीं, भीषण गर्मी के मद्देनजर मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। तेज धूप के कारण गर्म हवाओं ने बाइक सवारों को परेशान कर रखा है। लोग चेहरे को छुपा कर रोड पर चलते नजर आ रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार से लगातार अगले पांच दिन तक यलो अलर्ट जारी किया है, हालांकि गर्मी और लू की शुरुआत बुधवार से ही हो चुकी है। ऐसे में बृहस्पतिवार से दिल्ली वासियों को अधिक गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बृहस्पतिवार से दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच बुधवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके अगले दिन यानी बृहस्पतिवार को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में लू चलने के आसार हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। वहीं, इस दौरान शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। हालांकि, तापमान पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री ज्यादा है। वहीं, न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है। हवा में नमी का स्तर 42 से लेकर 18 प्रतिशत तक रहा। दिल्ली के रिज क्षेत्र सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।मौसम विभाग का अनुमान है कि अब गर्मी में तेजी से इजाफा होगा। मंगलवार को भी दिल्ली- एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का एयर इंडेक्स 209 रहा। एनसीआर में फरीदाबाद का एयर इंडेक्स 240, गाजियाबाद का 189, ग्रेटर नोएडा का 212, गुरुग्राम का 270 और नोएडा का 209 दर्ज किया गया। दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर 74 जबकि पीएम 10 का स्तर 224 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।

अब कोटे से नहीं होगा केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन, खत्म हुई प्रथा

नई दिल्ली । केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोटा प्रथा को खत्म कर दिया है. केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसको लेकर संशोधन के साथ नई गाइडलाइन्स भी जारी कर दी हैं. जो कोटा खत्म किए गए हैं उनमें सांसदों, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, केंद्रीय विद्यालय के सेवानिवृत कर्मचारियों और स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सहित प्रवेश से जुड़े करीब आधे दर्जन कोटे शामिल हैं. केंद्रीय विद्यालय में इस कोटे से भरी जाने वाली करीब 40 हजार सीटें मुक्त हो गई हैं. इनमें हर साल करीब 8 हजार सीटें सांसदों की सिफारिश से भरी जाती थीं. प्रत्येक सांसद को 10 सीटों का कोटा दिया गया था. विशेष कोटे से भरी जाने वाली ये सीटें स्कूलों में निर्धारित क्षमता के अतिरिक्त होती थीं. ऐसे में इस प्रवेश से केवी की गुणवत्ता सहित छात्र-शिक्षक अनुपात और कई अन्य मानक प्रभावित हो रहे थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कोटे की प्रथा को खत्म करने के लिए कहा था. इसके बाद सबसे पहले खुद शिक्षा मंत्री ने अपना कोटा खत्म किया साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन को प्रवेश से जुड़े विशेष कोटे की समीक्षा करने को कहा. केवीएस ने बीते दिनों कोटे पर रोक लगाने के साथ ही मामले की समीक्षा का फैसला लिया था. केवीएस ने मंगलवार को प्रवेश से जुड़े विशेष कोटे को खत्म करने के साथ ही प्रवेश को लेकर संशोधित गाइडलाइन भी जारी कीं. माना जा रहा है कि ये पहल से केंद्रीय विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार आएगा और इसमें सुधार आएगा. साथ इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों को लागू करने में भी सहूलियत होगी. देश में अभी करीब 1250 केंद्रीय विद्यालय हैं. इनका संचालन शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया जाता है. इन विद्यालयों की स्थापना मूलरूप से केंद्रीय कर्मचारियों जिनमें सेना, रेलवे आदि के लोग शामिल हैं उनके लिए की गई थी. पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है जिस तरह के वैक्सीन लगी है. लंबे समय बाद स्कूल खुले है जिससे बाद कोरोना के मामले बढ़े है. बच्चों मे कोरोना के मामले आ रहे है. लेकिन अब बच्चों को भी वैक्सीन मिल रही है सभी eligible बच्चों को टीका हमारी प्राथमिकता है जिसके लिए हमें स्कूल मे ड्राइव भी चलानी होगी. टीचर और परिजनों को भी इसके लिए तैयार रहना होगा. तीसरी लहर में कोरोना के बढ़ते मामले देखे हैं. उसके बाद भी हमने काम के साथ कोरोना को कंट्रोल किया था.

दिल्ली मेट्रो में मास्क पहन करें एंट्री, डीएमआरसी की फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों को फिर से किया गया एक्टिवेट

नई दिल्ली । कोरोना की चौथी लहर पूरे देश के साथ दिल्ली में भी पैर पसार रही है. कोरोना के पॉजिटिव केसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) ने भी एक बार फिर मेट्रो में मास्क पहनना जरूरी कर दिया है और बड़े पैमाने पर चेकिंग भी शुरू कर दिया है. डीएमआरसी द्वारा नियुक्त टीमें बिना मास्क पहने लोगों का चालान काट रही हैं. दिल्ली मेट्रो ट्रेनों के अंदर और स्टेशन परिसरों में अनाउंसमेंट और सोशल मीडिया सहित अन्य दूसरे प्रचार माध्यमों के जरिए इस नियम के लागू होने की जानकारी दे रही है. जबकि मेट्रो स्टेशन में प्रवेश देते समय सीआईएसएफ के द्वारा मास्क पहने हुए लोगों के सुनिश्चित करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है. दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों के मुताबिक डीडीएमए (दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) ने 23 अप्रैल से दिल्ली के सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. साथ ही इसका उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद, उसी दिन से मेट्रो में भी इस नियम को दोबारा लागू कर दिया गया है. यह नियम तोड़ने वालों के खिलाफ दिल्ली मेट्रो ऑपरेशन एंड मेंटनेंस एक्ट की धारा 59 के तहत कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे जा रहे हैं.

गार्डन गलेरिया मॉल के बार में हुई ब्रजेश की हत्या मामले में बार मैनेजर समेत सात लोग गिरफ्तार, दो फरार

नोएडा । नोएडा के गार्डन गैलरिया मॉल में स्थित एक रेस्त्रां में पार्टी करने गए एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार को सात लोगों को गिरफ्तार किया। इस घटना में संलिप्त दो लोग फरार हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि आरोपियों ने मृतक की जमकर पिटाई की। उसके सिर में गंभीर चोट आई जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। अपर पुलिस उपायुक्त (प्रथम जोन) रणविजय सिंह ने बताया कि सेक्टर-80 स्थित बैटरी बनाने वाली एक कंपनी जेएलएम में काम करने वाले सात लोग रविवार की रात सेक्टर 38-ए स्थित गार्डन गैलरिया मॉल के लास्ट लेमन नामक रेस्त्रां में पार्टी करने गए थे। रात 11 बजे के करीब पार्टी कर रहे लोगों तथा होटल के कर्मचारियों में बिल को लेकर विवाद हो गया। उन्होंने बताया कि 7,400 रुपये का बिल था। पार्टी करने वाले लोग बिल दिए बिना रेस्त्रां से बाहर निकल गए। इस बात को लेकर होटल के प्रबंधक तथा पार्टी करने वाले लोगों के बीच विवाद हुआ। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में

नोकझोंक हुई तथा देखते-देखते मारपीट शुरू हो गई। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि होटल कर्मचारियों ने पार्टी कर रहे लोगों के साथ मारपीट की। इस मारपीट में बृजेश राय (30) के सिर में गंभीर चोट आयी और उसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए प्रयाग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सोमवार को उसे मृत घोषित कर दिया। वह बिहार में छपरा जिले के हसनपुरा गांव का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राय के साथ पार्टी में आई युवती आरती ठाकुर ने सेक्टर-39 थाने में रेस्त्रा के प्रबंधक देवेंद्र सहित कई लोगों के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने इस घटना में शामिल नोएडा सेक्टर-15 निवासी सुंदर सिंह रावत, उत्तराखंड के कुमेर सिंह बंगारी, हिमांशु कुमार, दिल्ली के छतरपुर के निवासी देवेंद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के मेडी ठाकुर, नोएडा के गुड्डू सिंह और ग्रेटर नोएडा के कपिल उर्फ नाहर सिंह को गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में शामिल दो लोग अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले में होटल के मालिक की भूमिका की जांच कर रही है। इस बीच, मृतक बृजेश की पत्नी पूजा राय ने आरोप लगाया है कि पुलिस और उनके पति के साथ पार्टी करने गए लोगों ने इस मामले को उनसे काफी देर तक छुपाया। उन्होंने मुख्यमंत्री और कई नेताओं तथा वरिष्ठ अधिकारियों को ट्वीट कर इस मामले में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग की है। वह सेक्टर-132 स्थित डीपीएस स्कूल में अध्यापिका हैं।

कोरोना के नये मामले जून में चौथी लहर आने का संकेत दे रहे!

नई दिल्ली । देश में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर चिंता पैदा कर रहे हैं जिसको देखते हुए कई राज्य सरकारों ने पूर्व में दी गयी रियायतें वापस ले ली हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में कोविड-19 की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कोरोना के नये आंकड़ों की बात करें तो भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,927 नए मामले सामने आये हैं जिससे देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 16,279 पर पहुंच गई है। देखा जाये तो पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 643 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और पिछले 24 घंटे में देशभर में 32 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। हालांकि भारत में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.75 प्रतिशत है। फिर भी जिस तरह कोरोना के मामलों ने तेजी पकड़ी है उसको देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें बेहद सतर्क रुख अपना रही हैं। अभी एक दिन पहले ही भारत के औषधि महानियंत्रक ने पांच से 12 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 रोधी टीके 'कॉर्बेवैक्स' और छह से 12 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों के लिए 'कोवैक्सीन' टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। देश में चल रहे टीकाकरण अभियान की बात करें तो 86 फीसदी से अधिक वयस्क आबादी को कोविड-रोधी टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही देश में अब तक टीके की 188 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं।

दिल्ली के हालात

इस बीच, खबर है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बीच दिल्ली सरकार ने तय किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने समेत अन्य कोविड अनुकूल व्यवहारों के अनुपालन के लिए अभियान तेज किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि राजधानी के 11 जिलों में इस तरह के नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए अभी तक 70 से अधिक प्रवर्तन दल बनाये गये हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना हटाये जाने के बाद लोग बेफिक्र हो गये थे लेकिन सरकार ने जुर्माना फिर से लगा दिया है और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम आपको बता दें कि दिल्ली उन राज्यों में शुमार है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं।

दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 1,204 नए मामले सामने आए वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच, कोविड-19 के मामले बढ़ने और टीकाकरण प्रक्रिया का विस्तार होने के साथ दिल्ली सरकार ने कोविड अस्पतालों तथा जिला स्वास्थ्य केंद्रों में टीका लगाने, जांच, निगरानी और प्रबंधन समेत अन्य कामों के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों और कर्मियों की सेवाएं 30 जून तक जारी रखने का फैसला किया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव अजय बिष्ट ने इस संबंध में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करते हुए आदेश जारी किया।

मुंबई में भी मामले बढ़े

वहीं मुंबई में भी कोरोना के नये मामले तेजी से बढ़ने की खबर है। मुंबई में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 102 नये मामले सामने आए, जो कि इस साल 27 फरवरी के बाद एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं।

मुंबई में पिछले दो दिन में संक्रमण के मामलों की संख्या दोगुना से अधिक बढ़ गई क्योंकि रविवार को शहर में 45 मामले दर्ज किए गए थे।

कर्नाटक सतर्क

कर्नाटक में भी कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संकेत दिया है कि केंद्र की सलाह के आधार पर राज्य के हवाई अड्डों और सीमावर्ती जिलों में एहतियाती व निगरानी उपायों को फिर से लागू किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे एहतियाती उपायों का पालन करने की अपील की।

सम्पादकीय

एमवे के कारोबार में काला क्या है?

एमवे का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आपके घर की आमदनी 20 हजार प्रति महीना से ज्यादा है, तो आपने एमवे के सामानों को जरूर देखा होगा। रिश्तेदारों से इसके बारे में सुना होगा। बैग में भरकर एमवे ब्रांड से साबुन, क्रीम, परफ्यूम, दन्तमजन जैसे कई सामान दिखाने वालों से आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी। एमवे का सामान दिखाने वाले ने केवल सामान नहीं दिखाया होगा। कहा होगा कि सामान खरीदिये और एमवे के सदस्य भी बनिए। यह भी कहा होगा कि एमवे के सामान सबसे बढ़िया हैं। सामान खरीदकर आप सदस्य बनेंगे। सदस्य बनकर आप भी सामान बेचेंगे। दूसरे सामान खरीदेंगे और वह भी एमवे के सदस्य बनेंगे। इस तरह से हर सामान खरीदने वाला एमवे का सदस्य होगा। सबको कमीशन मिलेगा। सबकी कमाई होगी। जो जितना सदस्य बनाएगा वह उतना पैसा कमा कमायेगा। वह उतना अमीर बनेगा। इस सपने के साथ एमवे ने भारत में कारोबार किया। एमवे ने खूब कमाई की। लेकिन एमवे के सभी डिस्ट्रीब्यूटरों और सदस्यों ने नहीं। सिर्फ उनकी ही जेबें भारी हुई जो नेटवर्क चेन में सबसे ऊपर थे। इस कम्पनी पर भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय यानी इनफोर्समेंट डाइरेक्टोरेट ने हाल ही में छपा मारा है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने एमवे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसकी 757 करोड़ 77 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गयी सम्पति में कम्पनी की जमीन, फ़ैक्ट्री, गाड़ी और कई तरह की स्थाई और अस्थाई सम्पत्तियां शामिल हैं। जब्त करने का मतलब है कि एमवे इन सम्पतियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत की है। एमवे पर यह ईडी की प्रेस रिलीज बताती है कि एमवे ने 2002-03 से 2021-22 के दौरान अपने बिजनेस ऑपरेशन से 27 हजार 562 करोड़ रुपए कमाए। इनमें से 7,588 करोड़ रुपए उसने कमीशन के रूप में अपने अमेरिका और भारत के डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेंबर्स को दिए। एमवे एक अमेरिकी कंपनी है। एमवे ने साल 1995 -96 में भारत में कदम रखा था। कंपनी ने 21 करोड़ 39 लाख रूपये से शुरुआत की थी। इंवेस्टर्स और मूल संस्थाओं को लाभांश, रॉयल्टी और अन्य भुगतान के नाम पर 2020-21 तक 2,859.10 करोड़ रुपए भुगतान किये। यह एक तरह की पिरामिड स्कीम है। यहां प्रोडक्ट यानी सामान बेचने का काम नहीं किया जाता, बल्कि सदस्य बनाकर कमीशन से कमाई करने का काम किया जाता है। ग्रहाकों को लुभाने के लिए यह कंपनियां बड़े-बड़े सेमिनार करती है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह प्रचार करती है। इसके प्रचार का जरिया इसके ग्राहक होते हैं, जो केवल ग्राहक नहीं होते, बल्कि इसके सदस्य भी होते हैं। यह लोगों के सामने उन लोगों का उदाहरण पेश करते हैं, जो पिरमिड में सबसे ऊपर हैं। जिनकी अच्छी खासी कमाई है। इनके लाइफस्टाइल को दिखाकर अमीर बनने का सपना बेचा जाता है। एमवे पर श्रेष्ठ का कहना है कि एमवे ने अपने सामानों को बहुत ऊँचे कीमत पर बेचा। जबकि वैसे ही सामान जो एमवे के जरिये बेचे जा रहे था, उनकी कीमत दूसरे ब्रांड में कम थी। इस तरह का कारोबार लोगों की मेहनत की कमाई लूटने की तरह है। पिरामिड में सबसे ऊपर बैठे लोगों को कमीशन के जरिये बहुत कमाई होती है और जो नीचे मौजूद है उसकी कमाई कम रहती है या बिलकुल नहीं होती है। एमवे के मुताबिक यह कार्रवाई 2011 के जाँच के संबंध में है। तब से कंपनी विभाग के साथ सहयोग कर रही है। जानकरों का कहना है कि एमवे के कामकाज पर संदेह पैदा होता है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि दूसरे फ़ास्ट मूविंग कंस्यूमर गुड्स से जुड़े ब्रांड की कंपनियां एमवे से बड़ी हैं, लेकिन एमवे जितनी कैटेगरी का सामान बनाता है उतनी कैटेगरी का सामान दूसरे नहीं बनाते। उसका कारोबार भी उतना बड़ा नहीं है, जितना हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और नेशले का है। वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी उतना ख़र्च नहीं करता जितना दूसरी कंपनियां करती हैं। इनोवेशन के क्षेत्र में उसका खर्च दूसरों के मुकाबले कम है। तो कंपनी ऐसा कैसे कह सकती है कि उनके सामान सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं? वह सबसे क्वालिटी के अच्छे साबुन, क्रीम, दवाइयां बेचता है? इसलिए उसके कामकाज पर संदेह तो पैदा होता ही है। आर्थिक पत्रकार सुचेता दलाल कहती हैं कि एमवे की धांधली बहुत लम्बे समय से चलते आ रही है। पिरामिड स्कीम, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल सेलिंग को लेकर भारत में कोई सख्त कानून नहीं था। साल 2021 में इस सम्बन्ध में उपभोक्ता संरक्षण नियम बने। इसके तहत नियम बना कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कम्पनी यानी वैसी कम्पनी जो उपभोक्ताओं को सीधे अपना माल बेचती हैं वह कमीशन देने की शर्त पर अपना माल नहीं बेच सकती है। वह ऐसा नहीं कह सकती कि जो कम्पनी का माल खरीदेगा, वह कम्पनी का सदस्य बनेगा। इन कंपनियों के डायरेक्ट सेलर के पहचान से जुड़े कागज़ात कम्पनी अपने पास रखेगी। एक शिकायत निवारण तंत्र होगा। इसके तहत शिकायतों का निपटारा होगा। हाल फिलाहल ऐसा है कि कोई भी शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। एमवे का सामान खरीदने वाला जिससे सामान खरीदता है, उसके सिवाय नेटवर्क के अन्य सदस्यों को नहीं जानता। आर्थिक पत्रकार अंशुमन तिवारी का कहना है कि साल 2021 में कानून बना तब से एमवे के सामने चुनौतियां आनी शुरू हुईं। हालाँकि, यह एमवे पर साल 2011 के मामले को लेकर कार्रवाई की गयी है। लेकिन जिस स्तर पर सरकार ने एमवे पर कार्रवाई की है, उससे लगता है कि पूरा कारोबार सरकारी कार्रवाई के चपेट में आ गया है। यहां पर जो सबसे बड़ी चूक दिखती है वह यह है कि मल्टीलेवल और पिरामिड कारोबार का थंब रूल है कि कम्पनी 70 प्रतिशत से ज्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के बाहर बेचेंगी, यानि उन्हें बेचेगी जो कम्पनी के सदस्य नहीं होंगे। एमवे के कारोबार से लगता है उसने यही काम किया है। उसने माल बेचने से ज्यादा कमाई सदस्य बनाकर की है।

ट्विटर पर बदलाव की चहचहाहट

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने खरीद लिया है। ऐसा लगता है कि अरबपतियों का मीडिया कंपनियों को खरीदने और संचालित करने का यह दौर है। कुछ वर्ष पहले वाशिंगटन पोस्ट को अमेजॉन डॉट कॉम के जरिये अरबपति बनने वाले जेफ बेजोस ने खरीद लिया था। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा भी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मालिक हैं। मशहूर टाइम मैगजीन सेल्सफोर्स के सह-संस्थापक मार्क बेनीऑफ के हवाले है। एलन मस्क ट्विटर इंक को खरीदकर अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। दरअसल, कोई भी कंपनी जब शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाती है, तब एक तरह से अपने संस्थापक के हाथों से निकल जाती है। जिस जैक डॉरसी के सिर ट्विटर को शुरू करने का सेहरा बंधा है, वह खुद आज इस कंपनी से बाहर हैं। कारोबार के लिहाज से भी पिछले कुछ वर्षों में ट्विटर इंक काफी बदल चुकी है। बोर्ड भी निवेशकों के हितों को तरजीह देता है। इसलिए किसी बड़े निवेशक के प्रस्ताव को वह नकार नहीं पाता और आमतौर पर कंपनी बेच दी जाती है। ट्विटर के साथ काफी हद तक यही हुआ है। अब जब ट्विटर को नया मालिक मिल चुका है, तब कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसमें ढेर सारे बदलाव होंगे। इसकी एक बड़ी वजह खुद एलन मस्क हैं, जो काफी समय से ट्विटर की नीतियों की मुखालफत करते रहे हैं। वह मानते हैं कि ट्विटर बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है और देश-दुनिया को इसकी जरूरत है, लेकिन वह इसे सबके हाथों में पहुंचाना चाहते हैं। समाज और अर्थव्यवस्था के लिहाज से ट्विटर पर हर तरह के संवाद के वह पक्षधर हैं। एलन मस्क ट्विटर पर किसी को प्रतिबंधित करने के भी खिलाफ हैं। वह ट्विटर की नीतियों को संकुचित मानते हैं और कहते रहे हैं कि यह मंच उपलब्धियों के जिस मुकाम को छू सकता है, उससे काफी पीछे है। वह इसकी एक बड़ी वजह ट्विटर द्वारा लोगों पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को मानते हैं। वाकई, पिछले साल तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसने अपने मंच से बेदखल कर दिया था। खुद को सुपरपावर कहने वाले अमेरिका के पदासीन राष्ट्रपति को इस तरह से प्रतिबंधित करने का यह मीडिया इतिहास का पहला उदाहरण था। एलन मस्क न सिर्फ ऐसे कृत्यों के विरोधी हैं, बल्कि 'फ्री स्पीच' यानी अभिव्यक्ति की आजादी के पैरोकार भी हैं। उनका मानना है कि ट्विटर संवाद का मंच बने, न कि लोगों को निर्देशित करने का। इन सबको देखते हुए ही यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्विटर सही और गलत से परे, सबको अपनी बात कहने का मंच मुहैया कराएगा। मुमकिन है कि इसके बाद संबंधित देशों (जहां उसका उपयोग हो रहा होगा) के कानून इस पर कहीं अधिक मजबूती से आयद होंगे। ट्विटर की नाफरमानी का ही नतीजा था कि नाइजीरिया जैसे देश ने इसे अपने यहां प्रतिबंधित कर दिया था और कुछ महीनों के लिए 'कू' को अपना लिया था। भारत में भी कू जैसे विकल्प आने के बाद ट्विटर के प्रति लोगों की रुचि कुछ कम होती दिखी है। अगर फेसबुक, वाट्सएप, यू-ट्यूब जैसे मंचों से तुलना करें, तो सबसे कम उपयोगकर्ता ट्विटर के ही हैं, लेकिन इसका प्रभाव बाकी सबसे काफी ज्यादा है। यही वजह है कि भारत भी इन कंपनियों को देश में रहकर काम करने को कहता रहा है। विवाद के निपटारे के लिए चीफ कम्प्लाइंस ऑफिसर जैसे अधिकारियों की नियुक्ति करने पर वह हमेशा बल देता रहा है। मुमकिन है कि इस तरह की मांगें अब जल्द पूरी हो सकेंगी।

एलन मस्क ने कहा है कि रोबोट्स की मदद से चलाए जा रहे ट्विटर के अकाउंट बंद किए जाएंगे। इस तरह के अकाउंट्स सॉफ्टवेयर की सहायता से चलाए जाते हैं, जो किसी हैशटैग को देखकर खुद-ब-खुद उसे री-ट्वीट कर देता है। यह फर्जी अकाउंट से अलग होता है। इसी तरह, छद्म नामों का इस्तेमाल करके भी कुछ लोग अपना मतलब सीधा कर रहे हैं। एलन मस्क का मानना है कि जो व्यक्ति ट्विटर पर आए, वह मनुष्य हो, कोई स्वचालित मशीन नहीं। इसीलिए, यह भी कयास है कि निकट भविष्य में ट्विटर अकाउंट पर हमें केवाईसी (अपने ग्राहकों को जानो) कराने पड़ सकते हैं, जिसमें हम अपने राष्ट्रीय पहचान-पत्रों का इस्तेमाल करेंगे। अगर यह सब होता है, तो निस्संदेह ट्विटर उपयोगकर्ताओं की आपसी गाली-गलौज कम हो सकेगी, क्योंकि कोई नकाब ओढ़कर दूसरे से वाक्युद्ध नहीं कर सकेगा। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि कोई भी सोशल मीडिया मंच अब खुद को सुरक्षित न समझे। अगर कोई निवेशक किसी कंपनी में रुचि दिखाएगा, तो संभव है कि उसके मालिकान में हमें बदलाव देखने को मिल जाएं।

ऐसी कवायदों से कंपनी की नीतियों में किस तरह के परिवर्तन होंगे, यह तो नए मालिक की सोच पर निर्भर करेगा। लेकिन नए फेरबदल के बाद ट्विटर में यदि थोड़ी सफाई हो जाती है, तो यह सुखद होगा।

हालांकि, कुछ लोग इसे विरोधाभास भी मान सकते हैं कि एक तरफ तो एलन मस्क अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक हैं, और दूसरी तरफ जांचने-परखने के बाद ही ट्विटर उपयोगकर्ताओं को इस मंच के इस्तेमाल की अनुमति देने के हिमायती। लेकिन व्यापक अर्थों में देखें, तो इससे ट्विटर को भी फायदा होगा और आम उपयोगकर्ता कहीं संजीदगी से इस मंच पर अपने विचार साझा कर सकेंगे। संभव यह भी है कि आने वाले दिनों में हर उपयोगकर्ता को ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए निश्चित राशि जमा करने को कहा जाए, क्योंकि एलन मस्क यह कहते रहे हैं कि ट्विटर में अभी और पैसा बना सकने की क्षमता है। अगर ऐसा होता है, तब भी उपयोगकर्ता शायद ही इसका विरोध करना चाहेंगे, क्योंकि हम तब कहीं ज्यादा सार्थक बहस इस मंच पर देख सकेंगे। बहरहाल, अभी तमाम तरह की अटकलें फिजां में तैर रही हैं। देखना अब यह है कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है।

समाज का दोष सरकारों के सिर पर, संकीर्ण सोच से मुक्ति पाना आवश्यक

यह देखना दुखद है कि दलितों के साथ दुर्व्यवहार की वैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं, जैसी थम जानी चाहिए। बतौर उदाहरण बीते दिनों राजस्थान के जालौर जिले में एक दलित दंपती को मंदिर में पूजा करने से रोक दिया गया। चूंकि इस घटना का वीडियो वायरल हो गया तो पुलिस हरकत में आई और पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को अपवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ऐसी घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में रह-रहकर होती ही रहती हैं। वे कभी सुर्खियां बनती हैं और कभी नहीं। कभी दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता तो कभी उसकी बारात नहीं निकलने दी जाती। बीते सप्ताह ही यूपी के बुलंदशहर जिले के एक गांव में दलित दूल्हे की घुड़चढ़ी के वक्त पुलिस को उपस्थित रहना पड़ा और वह भी तब, जब दूल्हा खुद सीआरपीएफ में सिपाही है। उसने आशंका जताई थी कि उसे घुड़चढ़ी से रोका जा सकता है। इस आशंका का कारण अतीत में हुई ऐसी ही एक घटना है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। संयोग से पुलिस ने गंभीरता और तत्परता दिखाई और सब कुछ शांति से निपट गया। सदैव ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी-कभार पुलिस शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती या फिर उसके पास मामला पहुंचने के पहले ही अनहोनी हो जाती है। पुलिस के पास मामला जाए और वह कुछ न करे तो उसकी निंदा समझ में आती है, लेकिन आम तौर पर दलितों के साथ बुरे व्यवहार की जिन घटनाओं से पुलिस प्रशासन का कोई लेना-देना नहीं होता और यह भी शिकायत नहीं होती कि उसने समय पर सही कार्रवाई नहीं की, उनमें भी उसे और संबंधित राज्य की सरकार को खरी-खोटी सुनाई जाती है। ऐसा करते हुए यह भी देखा जाता है कि राज्य विशेष में किस दल की सरकार है। इसे वे भी देखते हैं, जो स्वयं को दलित हितों के लिए सदैव समर्पित और सक्रिय दिखाते हैं। निसंदेह राज्य सरकारों एवं उनके पुलिस प्रशासन को इसके लिए और सजग रहना चाहिए कि दलित या किसी भी कमजोर, वंचित तबके के व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो, लेकिन इतनी ही जिम्मेदारी समाज की भी तो है। क्या जालौर अथवा बुलंदशहर में जो कुछ हुआ, उसे रोकने के लिए सबसे पहले संबंधित गांव के असरदार लोगों को आगे नहीं आना चाहिए था? आखिर कहां थे ब्लाक, पंचायत सदस्य और प्रधान जी? इसी तरह क्या उन लोगों को सक्रिय नहीं होना चाहिए था, जो हिंदू समाज की एका की बात करते हैं और इस पर जोर देते हैं कि दलित, आदिवासी आदि हिंदू समाज का अविभाज्य अंग हैं? सवाल यह भी है कि धर्मगुरु गांव-गांव जाकर इसके लिए कोई अलख क्यों नहीं जगाते कि दलितों, आदिवासियों के साथ वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, जैसा होता है और जो सभ्य समाज को शर्मिंदा करने के साथ हिंदू समाज को कमजोर करने का काम करता है? समाज सुधार का काम केवल शासन-प्रशासन पर नहीं छोड़ा जा सकता।

जम्मू-कश्मीर के लिए नया सवेरा लेकर आयी है प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल ही में की गयी जम्मू-कश्मीर यात्रा पर इसलिए देश की निगाहें थीं, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वह पहली बार जम्मू-कश्मीर की धरती पर पहुंचे। उनकी इस यात्रा ने अनेक सकारात्मक संदेश दिये, शांति एवं विकास का माध्यम बना है। निश्चित ही उनकी यह यात्रा इस प्रांत में एक नई फिजां का सबब बनी है। जम्मू-कश्मीर हमारे देश का वो गहना है जिसे जब तक सम्पूर्ण भारत के साथ जोड़ा नहीं जाता, वहां शांति, आतंकमुक्ति एवं विकास की गंगा प्रवहमान नहीं होती, अधूरापन-सा नजर आता रहा है। इसलिए इसे शेष भारत के साथ हर दृष्टि से जोड़ा जाना महत्वपूर्ण है और यह कार्य मोदी एवं उनकी सरकार ने किया है। निश्चित रूप से वहां एक नया दौर शुरू किया है। इसके लिये जम्मू में मोदी ने पंचायत दिवस के अवसर पर केवल देश भर के पंचायत अधिकारियों को ही संबोधित नहीं किया, बल्कि इस केंद्र शासित प्रदेश की विभिन्न योजनाओं-परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करने के साथ कश्मीर एवं लद्दाख की जनता को भी यह संदेश दिया कि भारत सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अतीत की भूलों को सुधारना और भविष्य के निर्माण में सावधानी से आगे कदमों को बढ़ाना, हमारा संकल्प होना चाहिए। इसी संकल्प को मोदी ने सांबा के अपने उद्बोधन में व्यक्त किया है। नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में किए गए कार्यों का विवरण देकर यह भी रेखांकित किया कि अब कैसे विकास एवं जनकल्याण के काम तेजी से हो रहे हैं? न केवल विकास योजनाएं आकार ले रही हैं, बल्कि वहां शांति एवं सौहार्द का वातावरण बना है, आतंकवादी घटनाओं पर भी नियंत्रण किया जा सका है। मोदी की सरकार आने के बाद से जम्मू-कश्मीर के विकास को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सका है। सही समय पर केंद्र सरकार ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के साथ शेष वांछित कार्यों को पूरा करने के लिए वैसी ही दृढ़ता दिखाई है जैसी अनुच्छेद 370 हटाते समय दिखाई थी और देश के साथ दुनिया को यह संदेश दिया था कि कश्मीर में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं, कश्मीर भारत का ताज है और हमेशा रहेगा। मोदी की कश्मीर यात्रा इसलिये महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि वहां के लोगों ने साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय-विखण्डन, आतंकवाद तथा घोटालों के जंगल में एक लम्बा सफर तय करने के बाद अमन-शांति एवं विकास को साकार होते हुए देखा है। उनकी मानसिकता घायल थी तथा जिस विश्वास के धरातल पर उसकी सोच ठहरी हुई थी, वह भी हिली है। इन स्थितियों के बीच मोदी ने वहां के लोगों का विशेषतकर युवाओं का इन शब्दों के साथ ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया कि आपके माता-पिता, दादा-दादी को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उनका आपको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि वह अपने इस वचन को पूरा करके दिखाएंगे। आशा की जाती है कि उनकी इन बातों का सकारात्मक असर पड़ेगा। वैसे भी बीते कुछ समय में वहां अनेक ऐसे विकासमूलक काम हुए हैं, जो पहले नहीं हुए। विकास की योजनाएं तीव्रता से आकार ले रही है, इनमें विदेश से निवेश भी शामिल है। गौर करने लायक बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री के साथ वहां गए प्रतिनिधिमंडल में मुस्लिम ब्लॉक के एक महत्वपूर्ण सदस्य देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के टॉप बिजनेस लीडर्स भी शामिल थे, जो जम्मू-कश्मीर में निवेश में खास रुचि ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूएई की कंपनियां वहां 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करने वाली हैं। जम्मू-कश्मीर के लिए यह निश्चित ही नई बात होगी। इन सबके माध्यम से सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जम्मू-कश्मीर में शांति और सौहार्द के साथ लोकतंत्र और विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। जम्मू-कश्मीर को अशांत और संवेदनशील क्षेत्र बनाए रखने की कोशिश में लगे तत्वों को सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे ही संदेशों से होती है। जम्मू के सांबा क्षेत्र के एक छोटे से गांव पल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन एक उजाला है। शांति की स्थापना का संकल्प है। जनता को आश्वासन है विकास एवं आतंकमुक्त जीवन की ओर अग्रसर करने का। वहां की आम जनता की मानसिकता में जो बदलाव अनुभव किया जा रहा है उसमें सूझबूझ एवं सौहार्द की परिपक्वता दिखाई दे रही है। मोदी की यह यात्रा ऐसे मौके पर हुई है जब यह प्रांत विभिन्न चुनौतियों से जूझकर बाहर आ रहा है। वहां की राजनीति के मंच पर ऐसा कोई महान व्यक्तित्व नहीं है जो भ्रम-विभ्रम से प्रांत को उबार सके। वहां के तथाकथित संकीर्ण एवं पूर्वाग्रहग्रस्त नेतृत्व पर विश्वास टूट रहा है, कैसे ईमानदार, आधुनिक एवं राष्ट्रवादी सोच और कल्याणकारी दृष्टिकोण वाले प्रतिनिधियों का उदय हो सके, इस ओर ध्यान देना होगा। इस दिशा में मोदी की इस यात्रा की निर्णायक भूमिका बनेगी। निःसंदेह अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू-कश्मीर में बहुत कुछ बदला है और यह बदलाव दिखने भी लगा है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना शेष है। जो घटनाएं हो रही हैं वे शुभ का संकेत नहीं दे रही हैं। घाटी में अशांति, आतंकवादियों की हताशापूर्ण गतिविधियां, सीमापार से छेड़खानी- ये काफी कुछ बोल रही हैं। वहां देर-सबेर और संभवतः परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा चुनाव तो होंगे ही, लेकिन चुनाव कराने के पहले आतंकवाद पर पूरी तरह लगाम लगाने की जो चुनौती है, उससे भी पार पाना होगा। तमाम आतंकियों के सफाये के बाद भी कश्मीर में जिस तरह रह-रह कर आतंकी घटनाएं हो रही हैं, उनके चलते कश्मीरी हिंदुओं की वापसी फिलहाल संभव नहीं दिख रही। भले ही कुछ भी करना पड़े, इस काम को संभव बनाना होगा, क्योंकि तभी आतंकियों और उनके समर्थकों को यह संदेश जाएगा कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। यह भी सर्वथा उचित होगा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएं।मोदी की जम्मू यात्रा से कई उजाले हुए हैं। इस यात्रा से जम्मू-कश्मीर के निवासियों के साथ यहां की स्थिति पर चिंता जाहिर करने वाले बाहर के लोगों को भी रोशनी की किरणें दिखाई दी है, यह शुभ एवं श्रेयस्कर है। यह तथ्य भी सामने आया कि राज्य में लोकतंत्र को जीवंत करने का एक बड़ा काम इस बीच बगैर शोर-शराबे के पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 20000 करोड़ रुपये से ऊपर की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दिया यह तथ्य इस मामले में ज्यादा प्रासंगिक है कि पिछले छह महीने में राज्य में 80 लाख पर्यटक आए हैं। बहरहाल, जम्मू-कश्मीर के साथ परेशानियों का पुराना सिलसिला रहा है। खास तौर पर अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार भी सवालों के घेरे में हैं। 2018 से ही लगातार राष्ट्रपति शासन चल रहा है। ऐसे में शांति व्यवस्था और विकास संबंधी सरकार के दावों की भी असल परीक्षा इसी बात से होनी है कि वहां कितनी जल्दी विधानसभा चुनाव करवा कर निर्वाचित सरकार को शासन का जिम्मा सौंप दिया जाता है और लोगों को सामान्य लोकतांत्रिक माहौल मुहैया कराया जाता है। भारत की महानता उसकी विविधता में है। साम्प्रदायिकता एवं दलगत राजनीति का खेल, उसकी विविधता में एकता की पीठ में छुरा भोंकता रहा है, घाटी उसकी प्रतीक बनकर लहूलुहान रहा है। जब हम नये भारत-सशक्त भारत बनने की ओर अग्रसर हैं, विश्व के बहुत बड़े आर्थिक बाजार बनने जा रहे हैं, विश्व की एक शक्ति बनने की भूमिका तैयार करने जा रहे हैं, तब हमारे जम्मू-कश्मीर को जाति, धर्म व स्वार्थी राजनीति से बाहर निकलना सबसे बड़ी जरूरत है। इसी दिशा में घाटी को अग्रसर करने में मोदी सरकार के प्रयत्न सराहनीय एवं स्वागतयोग्य है। घाटी की कमजोर राजनीति एवं साम्प्रदायिक आग्रहों का फायदा पडोसी उठा रहे हैं, जिनके खुद के पांव जमीन पर नहीं वे आंख दिखाते रहे हैं।

यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन का अमृतकाल है

क्या देश की अदालतें इबादतगाह नहीं जुआघर हैं और संविधान को हमने विफल कर दिया है। क्या संसद और विधान सभाएं जिन्हें हम विधायिका कहते हैं, किसी मछली बाजार से ज्यादा कुछ भी नहीं है! और कार्यपालिका के बारे तो कुछ पूछिए ही नहीं। इसकी गाथा तो अंतहीन है। इसका एकमात्र चरित्र तो यही है कि इसके दामन दागदार हैं और जनता का इस पर कोई भरोसा नहीं। और लोकतंत्र के तीन प्रमुख स्तम्भ विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका पर अंकुश रखने, उसकी रखवाली करने और लोकतंत्र में जनता की आवाज बनने के लिए जिस मीडिया की भूमिका को चिन्हित किया गया था वह अब सबसे ज्यादा पतित, बेईमान और गुलाम हो गई है। मौजूदा समय में पत्रकारिता की नयी पहचान गोदी मीडिया के रूप में चर्चित है और पत्रकार समाज का सबसे बदनाम तबका। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। दुनिया को भारतीय मीडिया पर गर्व था और भारत के पत्रकार भी अपने सुकर्मों पर गीत गाय करते थे। लेकिन अब भारत का वही मीडिया मानो किसी कोठे की दासी बन गई हो। अधिकतर मीडिया का लोकतंत्र में न कोई आस्था है और न ही जनता के सवालों से उसका कोई लगाव। देश जलता रहे ,धर्म के नाम पर वोटों की तिजारत होती रहे और देश के मौजूदा सवालों पर विपक्ष चिल्लाता रहे लेकिन जब मीडिया इन सब बातों से अपना मुँह फेर ले और किसी निर्देश पर नर्तन करने लगे तो सारी लोकतंत्र की कहानी बेमानी ही लगती है। मौजूदा भारतीय लोकतंत्र की सही तस्वीर तो यही है जो ऊपर कही जा रही है। इस पर आप इतराइए या फिर रुदाली कीजिए लेकिन सच यही है कि आज जब देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है तो लोकतंत्र के चार प्रमुख स्तम्भों समेत तमाम तरह की संविधानिक और सरकारी संस्थाओं के लचर होने की गाथा भी गाई जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है? केवल हम इस बात को लेकर खुश हैं कि आजादी के 75 साल हो गए और इन सालों मे भारत दुनिया के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है। लेकिन यह कोई नहीं कहता कि इन 75 सालों में ही भारत का लोकतंत्र हांफने लगा है ,उसके मूल्य धूमिल हुए हैं। संस्थाओं की गरिमा तार -तार हुई है ,हमने अपना चरित्र खो दिया है और एक ऐसी लम्पट संस्कृति का वरण कर लिया है जिसमे नैतिकता है और न ही भविष्य। लोकतंत्र के इन 75 सालों में आदमी आदमी का दुश्मन बन गया है। राजनीतिक दल बटमार पार्टी के रूप में दौड़ती नजर आती है। जाति और धर्म के नाम पर पार्टियों की गोलबंदी है और एक जाति और धर्म के लोग दूसरी जाति और धर्म पर हमलावर है। सम्पूर्ण विकास की गाथा भले ही आज भी देश के कोने - कोने में नहीं पहुँच पायी हो। देश के वंचित और आदिवासी समाज को भले ही विकास की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता हो, भले ही देश के कई इलाके नक्सलवाद, चरमपंथ और आतंकवाद से ग्रसित हों लेकिन सरकारी दावे बहुत कुछ कहते नजर आते हैं। इसक एक सच ये भी है कि इसी देश में नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की भूमिका इतनी कमजोर, दागदार और लचर हो गई है कि जनता उनपर यकीन नहीं करती। इसे आप मौजूदा लोकतंत्र का गुण कहिये या फिर उसके ढहते होने का प्रमाण मानिए। और इसी दौर का सबसे बड़ा सच ये है कि भले ही देश के कई इलाके आज भी पानी की कमी, अशिक्षा, बीमारी, लूट खसोट और भूख से परेशान हो लेकिन वहाँ लोकतंत्र पहुँच गया है। पार्टियों के झंडे -बैनर सुदूर इलाके में भी आप को दिख जाएंगे और तरह -तरह के नेताओं की तस्वीर झोपड़पट्टियों की टाट पर लटकते मिल जायेंगे। 75 सालो की आजादी के बाद लोकतंत्र शहरी परकोटे को पार करते हुए गांव तक जरूर पहुंचा है लेकिन वही गांव आज भी न्याय पाने को लालायित है। कहने के लिए लोकतंत्र में जनता को तमाम अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या मौजूदा प्रधान मंत्री इसकी दस्तक दे पाएंगे? अगर ऐसा होता और संविधान की प्रस्तावना को ही हमारे सरकार ले लोग मानते तो देश के भीतर नफरत और घृणा की कहानी सामने नहीं आती। आज नफरत के माहौल पर लोकतंत्र रुदाली ही तो कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन ने कहा था कि सामाजिक ,आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे करोडो देशवासियों के लिए आज भी एक अधूरा सपना है। हमारे देश में सर्वाधिक तकनिकी कार्मिक हैं तो निरक्षरों की संख्या भी सबसे अधिक है। हमारे यहां विशाल माध्यम वर्ग हैं लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों और कुपोषित बच्चों की संख्या भी सर्वाधिक है। जहां बड़े -बड़े कारखाने हैं वही दरिद्रता और गंदगी भी है इस दुर्दशा को लेकर लोगों में रोष उग्र हिंसक हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। द्रौपदी के समय से ही हमारे महिलाओं को बदले की भावना से सार्वजानिक चीर -हरण और अपमान का शिकार बनाया। ग्रामीण क्षेत्रों में दलित महिलाओं के लिए अब भी यह आम बात है ,परन्तु हैरानी की बात तो यह कि हम अब भी चुप हैं। समाज के कमजोर वर्गों से हमें ऊबना नहीं चाहिए अन्यथा जैसा आंबेडकर ने कहा था कि हमारे लोकतंत्र की ईमारत गोबर पर बने महल जैसी हो जाएगी। यह दिल्ली कभी इंद्रप्रस्थ थी, जहां कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का धर्मयुद्ध लड़ा गया था। यही दिल्ली कभी सूफी-संतों की दुनिया थी, जहां एक से बढ़कर एक सूफी-संत डेरा जमाए रहते थे। यहीं थे बहादुरशाह जफर और स्थापित थी उनकी मुगलिया सल्तनत। इसी दिल्ली में गालिब और मीर की महफिलें सजती थीं और गूंजती थीं गांधी की प्रार्थनाएं 'ईश्वर अल्लाह तेरो नाम!' इसी दिल्ली में लालकिले की प्राचीर से 'आधुनिक भारत के जनक' पंडित जवाहर लाल नेहरू आधुनिक भारत के सपने देखते थे। यहीं के काफी हाउस, मंडी हाउस और जेएनयू से लेकर संसद तक सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर गंभीर बहसें हुआ करती थीं। यह वही दिल्ली है, जहां महिलाओं को मां-बहन के रूप में देखा जाता था और इसी दिल्ली में 'अंग' से 'अंग' सट जाने पर तलवारें खिंच जाती थीं, लेकिन अब यहां ये सब नहीं होता! लोकतंत्र के सारे स्तम्भ यह सब देखते जरूर हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं। लोकतंत्र के पतन का इससे उदहारण और क्या दिया जा सकता है। 21वीं सदी में दिल्ली भी बदल गई है। दिल्ली में गर्मी है, तपिश है और खुलापन के साथ लूट, दुष्कर्म, हत्या, दलाली, सेक्स बाजार और झटपट धनी बन जाने की ऐसी होड़ लगी है, मानो हम कुएं में गिरने को आतुर हैं। और इस खेल में लोकतंत्र के पिलरों की बड़ी भूमिका है। दिल्ली का वर्तमान वह नहीं है, जो उसका अतीत था! अब यहां नए जमाने के 'रईस' रहते हैं। उनके पास पैसा है, सत्ता है और पुलिस की फौज है। कहते हैं कि गर्मी से गर्मी कटती है। इस शहर में गर्मी निकालने के कई 'खेल' हैं। और इस खेल में पूरा लोकतंत्र शामिल है। क्या नेता ,क्या न्यायधीश ,क्या ब्यूरोक्रैट और क्या मीडिया से जुड़े लोग। लोकतंत्र के अवसान के साथ ही लगता है भारत की संस्कृति भी बेहाया और नंगी हो चली है। किसी भी शताब्दी का कोई वर्ग इतना बेहया नहीं होगा, जितना हमारा उच्च और मध्यम वर्ग है। यही वह वर्ग है, जो बाजार के निशाने पर है और बाजार के लिए एक कमोडिटी है। अजीब से अर्द्धनग्न कपड़े पहनकर इठलाती औरत में जितना औरताना सौंदर्य या अस्मिता है, उतनी ही मर्दानगी उस पुरुष में भी है, जो सूट, ब्लेजर पहने ब्रीफकेस लेकर चमचमाते जूते पहने, कार में जाता दिखता है। दिल्ली में बैग उठाए व्यस्त सफल दिखता पुरुष अपने बुद्धिबल और बाहुबल के दम पर कुछ नहीं रचता! दरअसल, वह दलाल है, लाइजनर है, उसकी समृद्धि और सफलता उतनी ही व्यक्तित्वहीन, सौंदर्यहीन है जितनी हमारे देश की तकनीकी और वैज्ञानिक तरक्की के किस्से। एक दलाल सभ्यता के 'लार' टपकाऊ विज्ञापनों की दुनिया के आधार पर इतिहास नहीं रचा जाएगा, लेकिन यह शायद हमारी सभ्यता के सबसे प्रामाणिक साक्ष्य हैं। खुशकिस्मती है कि इन्हें साक्ष्य की तरह देखा जाएगा, तब शर्म से डूब मरने के लिए हम नहीं होंगे। और यह सब भी लोकतंत्र के नाम पर ही हो रहा है और इसमें बड़ी भूमिका लोकतंत्र के चार स्तम्भों समेत उन संविधानिक और सरकारी संस्थाओं की भी है जिसला लगातार छरण होता जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र की ढहती संस्थाओं की कहानी कोई आज से शुरू नहीं हुई है। विधायिका में छरण तो 67 से ही शुरू हो गई थी। 80 के दशक में और भी बलवती हुई। . नेताओं के चरित्र बदले। राजनीति बदली तो अपराध का राजनीतिकरण शुरू हुआ। बाहुबल के दम पर वोट लुटे जाने लगे।

भ्रष्ट ई.ई अशोक कुमार के भ्रष्टाचार की कमान बी.डी.शर्मा के हाथों में

सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, सी.डी-11 में करोड़ो का भ्रष्टाचार.....सी.बी.आई जांच की मांग l

कार्यपालक, सहायक व कनिष्ठ अभियंता बने भ्रष्टाचारी नंम्बर-1

सी.डी-11 के पूर्व ई.ई अशोक कुमार, ए.ई, जे.ई ने किए करोड़ो के वारे न्यारे...

विकास एवं निर्माण कार्यो में घोटाला कर लगाई गई व लगाई जा रही, बेहद घटिया निर्माण सामग्री की शिकायतो के आगे केजरीवाल प्रशासन ने टेके घुटने

पूर्व ई.ई अशोक कुमार के बाद ई.ई बी.डी.शर्मा डूबे भ्रष्टाचार के आकंड में कमिशन खोरी का सिलसिला लगातार जारी

निलोठी एक्सटेंशन, चन्द्र विहार के बड़े नाले पर नये पुल के निर्माण कार्य में किया करोड़ो का घोटाला

श्री खंडा साहिब चौक, चंदर विहार में कई पार्को के विकास एवं निर्माण कार्य में किया करोड़ो का घोटाला

शिकायते होती रही परन्तु भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, आज भी नही लगी रोक !

अध्यक्षः अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा

विज्ञापन-जनहित में जारी.....

उपायुक्त, रोहिणी जोन, उ.दि.न.नि के संरक्षण में

पीरागढ़ी, वार्ड-50, वर्क्स विभाग का काली सड़क घोटाला व भ्रष्टाचार की सी.बी.आई जांच की मांग।

कार्यपालक, सहायक व कनिष्ठ अभियंता बने "अडानी"

एम-2, वर्क्स विभाग, रोहिणी जोन के ई.ई श्री रमेश चन्द्रा, ए.ई श्री महिपाल सिंह, जे.ई श्री गौरव सैनी की मिलीभगत से किए करोड़ो के घोटाले....

पीरागढ़ी वार्ड-50 में किये जा रहे व किये गए काली सड़क निर्माण में लगाई बेहद घटिया निर्माण सामग्री, एमसीडी को लगाया अभियंताओं ने करोड़ो का चूना, घटिया सड़क निर्माण कार्य से।

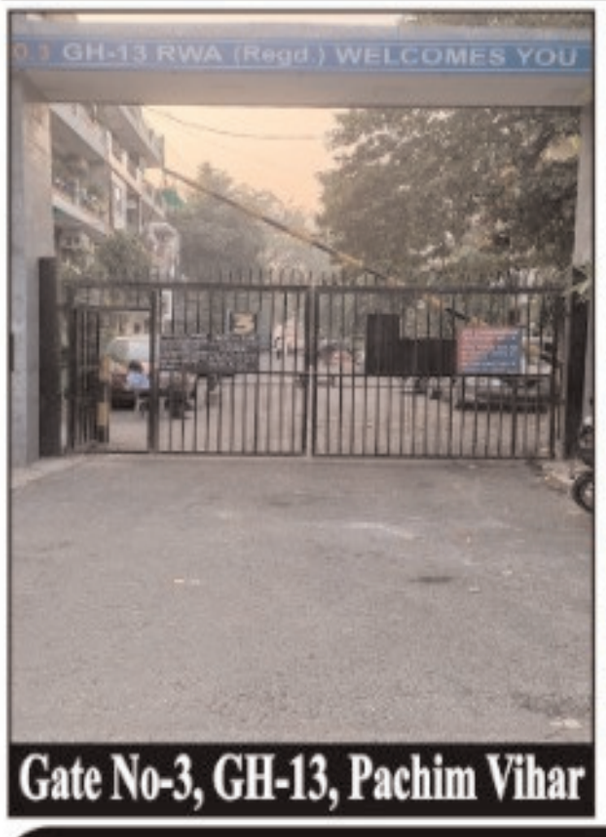

Gate No-3, GH-13, Pachim Vihar

Gate No-8, GH-14, Pachim Vihar

Gate No-3, GH-14, Pachim Vihar

भैरा एन्कलेव, पश्चिम विहार

विकास एवं निर्माण की काली कमाई से उपायुक्त, रोहिणी जोन, वर्क्स विभाग, ई.ई श्री रमेश चन्द्रा, ए.ई श्री महिपाल सिंह, जे.ई श्री गौरव सैनी बने 'अडानी'

करोड़ो रूपये की बेनामी सम्पत्ति खरीदी अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम महंगी-महंगी लग्जरी कारों से चलते है, स्वयं व इनके परिवार

एप्पल का मोबाईल व लेपटॉप और पी.पी.डिजाईनर के कपड़े, रोलेक्स की घड़ी, बूची के जूते, लग्जरी कारो स्वंय व परिवार के लिए प्राईवेट ड्राइवर २०-२० हजार प्रतिमाह, शाम का डिनर बड़े रेस्टुरेंट, होटल और क्लबों और लाखों की ज्वैलरी और अडानी की तरह आलीशान जिन्दगी जी रहे है।

अध्यक्षः अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा

विज्ञापन-जनहित में जारी.....

दुनिया के 10 अजीबो-गरीब अजूबे

दुनिया में बहुत सी ऐसी इमारते,जगहें,नदीयां है जिनकी अपनी कोई खास बात है और इनकी खासीयत के कारण ही लोग दूर-दूर से इनके देखने के लिए आते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के मशहूर आठ अजूबों के अलावा भी इस विश्व में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिनकी खूबसूरती को किसी और के साथ आंकना नामुमकिन है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अजूबों के बारे में...

1. Banaue Rice Terraces, Philippines

फिलिपिनी इस खेत को दुनिया का अजूबा ही मानते हैं।200 साल पहले बनाए गए इस खेत की खासीयत यह है कि इसके पहाड़ो को हाथों से काटकर बनाया गया है।

2. Bagan, Myanmar

एशिया में सबसे ज़्यादा मंदिर वाले शहरों में इसका नाम लिया जाता है। इस शहर के एक बागान में प्रचीन समय में 10000 से भी ज्यादा मंदिर थे। इस वक्त इसमें 2000 मंदिर ही हैं। जो बौद्ध धर्म के गौरव का प्रतीक है। इनकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहा आते हैं।

3. Torun, Poland

इस शहर में टूरिस्ट मध्यकालीन युग की बनी हुई ईमारतों को देखने के लिए आते हैं।

4. Meteora, Greece

ग्रीस को मेटोरा प्रचीन मठों के लिए दुनियाभर में मशहूर है। यहां पर 6 मठ ऊंची चट्टानों पर बने हुए हैं, जो खूबसूरती का अलग नजारा ही पेश करती हैं।

5. Tower of Hercules, Spain

इस टॉवर का इतिहास मिस्र के पिरामिडों जितना ही पुराना है। यह सिर्फ एक लाइट हाउस ही है लेकिन यह अब तक इस्तेमाल होने वाला सबसे पुराना लाइट हाउस है।

6. Library of Celsus, Turkey

यूनानी वास्तुकला से बनी यह लाइब्रेरी रोमन सेनेटर श्वस्रद्बद्बद्बष्द्ध को समर्पित है। यह एतिहासिक पर्यटक स्थानों में से एक है।

7. Tunnel of Love, Ukraine

यूक्रेन के च्द्यद्ग1द्वड्ढ का यह रास्ता 3 किमी तक पेड़ों से ढ़का हुआ है। जिसके कारण यह पर्यटकों की पसंदीदा जगह है।

8. Enchanted Well at Chapada Diamantina National Park, Brazil

इस जगह का नजारा जन्नत से कम नही है। यह पार्क जमीन से लगभग 100 फीट नीचे बना है और यहा पर पेडों की जडों को साफ देखा जा सकता है। सूरज की रोशनी इनके छोटे-छोटे छेदों के जरिए जब अंदर आती है तो पानी पर पड़ने से चारों और नीले रंग की रोशनी फैल जाती है।

9. Wisteria Tunnel at Kawachi Fuji Gardens, Japan

बसंत के दिनो विसटेरिया में हर तरफ फूल ही फूल खिल जाते हैं।

10. Red beach, Panjin, China

चीन के पंजीन में रैड बीच दुनिया भर में मशहूर है। यहां पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। यह असल में कोई बीच नही है सिर्फ समुद्र के ऊपर उगी सीवीड है,जो बसंत में लाल और गर्मियों में हरी चादर की तरह फ़ैल जाती है

ये हैं दुनिया के 5 सबसे पुराने शहर !

आपने दुनिया के ऐसे बहुत से देशो के बारे में सुना होगा जो बहुत खूबसूरत है या फिर छोटे,कम जनसंख्या,ज्यादा ट्रैफिक या फिर किसी और कारणों के कारण दुनिया भर में जाने जाते हैं लेकिन आज हम आपको ऐसे शहरों के बारें में बता रहें हैं जो विश्व के सबसे पुराने शहर हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार यह शहर लगभग 11000 साल भी पुराने हैं।

1. बाइब्लोस (लेबनान)

यह शहर दुनिया के सबसे प्रचीन शहरों में से एक है। इसको पहले जिबल के नाम से भी जाना जाता था। इस शहर में लोग खासतोर पर प्राचीन मंदिरों, कैसल और सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च देखने आते हैं। 2. जेरिको सिटी ऑफ पाम ट्रीज इस शहर की आबादी लगभग 20 हजार है। यह छोटा सा कस्बा समय -समय पर अलग-अलग देशों का गुलाम रह चुका है। जॉर्डन,इजरायल,फीलिस्तीन देश भी इस पर राज कर चुके हैं। हिब्रू बाइबिल में जेरिको सिटी ऑफ पाम ट्रीज के नाम से इसके जिक्र किया गया है।

3. एलेप्पो (सीरिया)

यह फहर भी लगभग 6300 साल पुराना है। यह सीरिया का सबसे बड़ा नगर है जो प्राचीन काल से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा।

4. दमास्कस (सीरिया)

सीरिया के एक और शहर दमास्कस भी अपने पुराने इतिहास के कारण बहुत महत्वपूण है। 5. सुसा (ईरान)

65000 की आबादी वाला यह शहर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए काफी प्रसिद्ध है।

दुनिया के10 ऐसे ऐतिहासिक स्थान
जहां लगती हैं पर्यटकों की भीड़

हर देश का अपना कुछ ना कुछ इतिहास और ऐतिहासिक इमारतें होती हैं। अगर इन बिल्डिंग की बात की जाएं तो इनकी नायाब खूबसूरती को देखकर आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। यह किसी करिश्में से कम नहीं लगती और इनकी खास बात यह है कि अपने- अपने देश के इन सालों पुराने ऐतिहासिक स्थानों को हर सरकार हमेशा के लिए संभाल करना चाहती है। आज हम दुनिया के कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थानों की बात कर रहें हैं जिसके कारण विश्व भर से लोग इनको देखने के लिए इन देशों में जाते हैं।

1. माचू पिच्चू, पेरू

दक्षिण अमेरिकी में स्थित माचू पिच्चू में पेरू बहुत मशहूर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यह इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। माचू पिच्चू को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया।

2. शेख जाएद मस्जिद, अबु धाबी, यूएई शीशे की तरह जगमगाती यह मस्जिद दुनिया की सबसे सुंदर मस्जिद है। सफेद रंग से बनी ईमारत कारीगरी के नायाब नमूना है। इसे बनाने के लिए भारत मलेशिया, तुर्की, मोरक्को, चीन, ईरान, यूके, न्यूजीलैंड और ग्रीस से कारीगर बुलाए गए थे। मस्जिद के सेंट्रल हॉल में 9 टन वजन का झूमर लगाया गया है।

3. अंकोरवाट मंदिर

अंकोरवाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में से एक है और सनातनी लोगों का तीर्थ स्थान है।

4. सेंट पीटर बेसिलिका वेटिकन सिटी, इटली

इटली की वेटिकन सिटी में यह चर्च दुनिया में सबसे बड़े चर्चों में से एक है।

5. ताजमहल, आगरा, भारत ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है। सफेद संगमरमर से बनाई इस ईमारत को दुनिया के आठ अजूबों में शामिल किया गया है।

6. कोरदोबा की मस्जिद-गिरजा, कोरदोबा, स्पेन इस मस्जिद में 850 रंगीन ग्रेनाइट जैस्पर और संगमरमर के खंभें हैं जो इसकी खूबसरती में चार चांद लगाती है।

7. चर्च ऑफ द सेवियर ऑन ब्ल्ड, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस इसकी खास बात यह है कि धूप पड़ते ही ये चर्च डगमगा उठती है। इसे 1881 में उस जगह बनाया गया था जहाम पर राजा अलेक्जेंडर की हत्या की गई थी।

8. अल हम्रा, ग्रानादा, स्पेन

यह स्पेन का ऐतिहीसिक महल है। इसे विश्व धरोहर के रूप में संभाल कर रखने के लिए कुछ कई बार पुनर्निर्माण भी कराया गया है।

9. लिंकन मेमोरियल रिफलेक्टिंग पूल, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया लिंकन मेमोरियल रिफलेक्टिंग पूल वाशिंगटन डीसी के कई रिफलेक्टिंग पूल्स के मुकाबले बहुत बड़ा है। इसे खाल वॉक करने वालों के लिए बनाया गया था।

10. ड्यूमो डी मिलानो, मिलान इटली

ड्यूमो डी मिलानो इटली का कैथेड्रल चर्च है। यह मिलान के आर्कबिशप की सीट है, जिसे पूरा बनने में लगभग छह सदियां लग गईं। यह दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया। सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो0 : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2001/08863)

निगम में भाजपा की छवि को कालिक पोत रहे है भ्रष्ट अभियंता

करोल बाग जोन, भवन विभाग बना भ्रष्टाचार का अड्डा!

अवैध निर्माण की काली कमाई से अभियंता से उपायुक्त तक बने "अडानी"

उ.दि.न.नि के मुख्य सतर्कता अधिकारी मंगेश कश्यप बने मूक दर्शक कब तक चलता रहेगा भ्रष्टाचार का खेल

करोल बाग, नई दिल्ली

करोल बाग, नई दिल्ली

करोल बाग, नई दिल्ली

करोल बाग, नई दिल्ली

करोल बाग, नई दिल्ली

करोल बाग, नई दिल्ली

करोल बाग जोन में बिल्डर माफिया का राज सारे वार्ड बनते जा रहे है स्लम युक्त हर वार्ड में चार से पांच मंजिला, बेसमेन्ट सहित अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। अभियंताओं की काली कमाई चल-अचल व बेनामी सम्पत्ति की श्रीमान निदेशक जी, सीबीआई, भारत सरकार से जांच की मांग।

अध्यक्ष: अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा

विज्ञापन-जनहित में जारी.....